दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश से एक साथ प्रकाशित ››› दिल्ली ››› गाजियाबाद ››› नोएडा ››› ग्रेटर नोएडा ››› हापुड़ ››› अमरोहा ››› बागपत ››› मेरठ ››› मुजफ्फर नगर ››› बिजनौर ››› मुरादाबाद ››› बुलंदशहर ››› अलीगढ़ ››› फरीदाबाद ››› गुड़गांव ››› सोनीपत

RNI-UPHIN/2009/30721

दिल्ली
अधिकतम तापमान 33 डिग्री
न्युनतम तापमान 27 डिग्री
एनसीआर
अधिकतम तापमान 32 डिग्री
न्युनतम तापमान 26 डिग्री

शुक्रवार 22 अगस्त 2025
सुर्योदय प्रात: 05 :54 बजे
सूर्यास्त सांय 16 : 54 बजे

www.khabariya.com

एनसीआर टुडे

करंट न्यूज करंट व्यूज

पृष्ठ 4 महामहिम की जवाबदेही से आदिवासी क्षेत्रों को नई ताकत

उत्तर प्रदेश और दिल्ली से एक साथ प्रकाशित | वर्ष: 16 | अंक : 307 | गाजियाबाद, शुक्रवार 22 अगस्त 2025 | मूल्य : ₹ 2 | पेज : 06 | विक्रमी संवत् 2081 | युगाब्द 5126 | शाक 1946

मानसून सत्र में लोकसभा में बारह विधेयक पारित हुए : बिरला

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷। ओम बिरला ने कहा कि मानसून सत्र में 14 विधेयक पुरःस्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। श्री बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले गुरुवार को अपने वक्तव्य में कहा कि इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। गत 28 और 29 जुलाई को 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर के साथ हुआ। 18 अगश्त को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा आरंभ की गयी। उन्होंने कहा कि इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर हेतु लिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा और संवाद करेंगे।

कपिल सिब्बल ने केंद्र को घेरा

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का प्रश्ताव रखने वाला विधेयक संविधान के लिए दीमक का काम करेगा। सिब्बल ने कहा कि ऐसा लगता है कि इन विधेयकों का उद्देश्य विपक्षी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाना है और आरोप लगाया कि सरकार संविधान के मूल सिद्धांतों को नष्ट कर रही है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इन विधेयकों को पारित नहीं करा पाएगी, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जो सरकार के पास नहीं है।

जीएसटी में बड़े बदलाव को जीओएम की मंजूरी

● 5 और 18 फीसदी के स्लैब को मंत्री समूह ने दी मंजूरी

4 की जगह 2 स्लैब होंगे, रोजाना वाली चीजें सस्ती होंगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 5 फीसदी और 18 फीसदी के स्लैब को मंजूरी दे दी है। लग्जरी आइटम्स 40 फीसदी के दायरे में आएंगे। जीओएम के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5, 12, 18, और 28 फीसदी होते हैं। जीओएम की बैठक पर इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा- हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें 12 और 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात है। सभी ने केंद्र के प्रस्तावों पर अपने सुझाव दिए। कुछ राज्यों ने कुछ आपत्तियां भी जताई। इसे जीएसटी काउंसिल के पास भेजा गया है जो इस पर फैसला लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दीवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोगों को बहुत फायदा होगा। सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट आदि सस्ते होंगे।

● ये सामान सस्ते होंगे, इन पर टैक्स 28 से 18 फीसदी होगा- सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, रेडी-मिक्स कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, निजी विमान, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, चीनी सिरप, कॉफी कॉन्सेंट्रेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, एल्युमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट, डेंटल फ्लॉस। जीएसटी में अलग-अलग राज्यों के वरिष्ठ मंत्री सरकार की एक विशेष समिति है, जिसमें अलग-अलग राज्यों के सीनियर मिनिस्टर शामिल होते हैं। इसे जीएसटी से जुड़े जटिल मुद्दों, जैसे टैक्स रेट बदलना या राजस्व विश्लेषण, पर चर्चा और सिफारिशें देने के लिए बनाया जाता है। यह जीएसटी काउंसिल को सुझाव देता है, जो अंतिम फैसला लेती है। इनमें 6 से 13 सदस्य तक हो सकते हैं। जैसे जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन जीएसटी में 6 सदस्य हैं। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, और केरल के प्रतिनिधि शामिल हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी जीएसटी में 13 सदस्य हैं। जीएसटी काउंसिल में केंद्र और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि (आमतौर पर वित्त मंत्री) शामिल होते हैं।

उपराष्ट्रपति पद के लिए बी. सुदर्शन का नामांकन पत्र दाखिल

● सोनिया गांधी समेत 80 नेता बने प्रस्तावक, दिखाई विपक्षी एकता

नई दिल्ली (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बुधवार देर रात इंडिया ब्लॉक के 80 नेताओं ने रेड्डी के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में अपने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाले नेताओं में प्रमुख रूप से सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी से सांसद

रामगोपाल यादव जैसे नेता प्रमुख थे। इससे पहले रेड्डी को इंडिया ब्लॉक की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने की। उन्होंने कहा रेड्डी को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक बताया। जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभा पति का पद खाली हुआ है। इसके बाद सत्ताधारी एनडीए की तरफ से राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया था।

भारत के साथ नहीं कर सकते दुश्मन जैसा बर्ताव

घर में ही घिर गए डोनाल्ड ट्रंप, निकी हेली ने चेताया

वाशिंगटन (एजेंसी)। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले दो दशक में सबसे निचले दौर पर हैं। कुछ महीने पहले एक-दूसरे के और करीब आते दिख रहे यह दो लोकतांत्रिक देश अब अलग-अलग पक्ष में दिख रहे हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने चेतावनी दी है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के संबंध टूटने की कगार पर है और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच अगर वाशिंगटन, नई दिल्ली को खो देता है, तो यह किसी रणनीतिक आपदा से कम नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप प्रशासन को भारत के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव करने के लिए भी चेतावनी दी। हेली ने कहा कि अमेरिका को जल्दी से जल्दी दोनों देशों के संबंधों में सुधार करना चाहिए। न्यूजवीक में प्रकाशित एक आर्टिकल में हेली ने कहा कि ट्रंप प्रशासन रूसी तेल और टैरिफ विवादों के बीच भारत और अमेरिका के बीच दरार पैदा नहीं कर सकता, हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच दरार पैदा करने की अनुमति उन्हें नहीं दे सकते। उन्होंने लिखा, अमेरिका को सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। चीन का सामना करने के लिए अमेरिका का भारत के रूप में एक मित्र होना जरूरी है।

कांग्रेस के युवाओं नहीं दिया जाता है बोलने का मौका

● पीएम मोदी बोले- 'परिवार की असुरक्षा' पड़ रही है भारी

कहा-राहुल गांधी कांग्रेस के युवा नेताओं से घबराते हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम मोदी ने चाय मीटिंग में एनडीए नेताओं के सामने कांग्रेस के कई युवा नेताओं की तारीफ की और कहा कि विपक्ष खासकर कांग्रेस में कई युवा नेता काफी टैलेंटेड हैं, लेकिन 'परिवार की असुरक्षा' की वजह से उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। इंडिया टुडे के सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस तरह के युवा

नेताओं की मौजूदगी राहुल गांधी गांधी को असुरक्षित और घबराहट महसूस करवा रही होगी। इस बैठक में विपक्ष का कोई भी सांसद शामिल नहीं हुआ और सिर्फ एनडीए के ही सदस्य मौजूद थे। पीएम मोदी ने आज खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र को भी अच्छा बताया और कहा कि इसमें कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए।

मदरसा शिक्षकों का नीतिश के सामने हंगामा

पटना (एजेंसी)। पटना के बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में नीतिश कुमार के सामने गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में नीतिश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की। लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन नहीं दे पाए। इसके बाद उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के भाषण के बाद आक्रोशित शिक्षक पर्चे लहराने लगे।

भारत को खुद की आत्मरक्षा का है पूरा अधिकार:जयशंकर

● रूस की धरती से पाकिस्तान को दिया सीधा संदेश

विदेश मंत्री ने रूसी तेल पर अमेरिका को भी खूब सुनाया

मॉस्को (एजेंसी)। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर रूस की जमीन से दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है। जयशंकर ने गुरुवार को आतंकवाद के प्रति भारत के जीरो टॉलरेंस के रुख की पुष्टि करते हुए कहा कि अपनी रक्षा करना किसी भी संप्रभु देश का अधिकार है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस

वार्ता में जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली और मॉस्को ने मिलकर आतंकवाद से लड़ने का संकल्प लिया है। रूस के दौरे पर पहुंचे जयशंकर के इस रुख को पाकिस्तान के लिए संदेश की तरह देखा जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने स्टेटमेंट में कहा, आतंकवाद से बचाव करना भारत का संप्रभु अधिकार है। हम हर रूप में आतंकवाद की निंदा करते हैं।

डिफेंस सेक्टर में 'आत्मनिर्भरता' की ओर बढ़ रहा भारत

तेल अवीव (एजेंसी)। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी औद्योगिक और सुरक्षा नीतियों में एक रणनीतिक बदलाव किया है। भारत ने दुनिया के बड़े रक्षा खरीदार की छवि को बदलते हुए इसने आत्मनिर्भर भारत पहल शुरू की, जो आज देश के आर्थिक, औद्योगित और सुरक्षा एजेंडे को आकार दे रही है। भारत ने उन्नत रक्षा प्रणालियों के लिए घरेलू अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दी है और आयात पर निर्भरता कम

की है। रक्षा क्षेत्र में भारत की इस मेक इन इंडिया पहल में इजरायल उसका अहम सहयोगी बनकर उभरा है। भारत-इजरायल सुरक्षा प्रौद्योगिकी साझेदारी व्यवहार में तकनीकी राष्ट्रवाद का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इजरायल के साथ भारत ने रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी विकसित की है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ संयुक्त विकास शामिल है। उल्लेखनीय संयुक्त परियोजनाओं में बराक-8 मिसाइल शामिल है, जिसे इजरायल साथ में बनाएगा।

बिल पेंडिंग का मामला

एससी में कहा-अदालत हर समस्या का समाधान नहीं

राज्य कोर्ट की बजाय बातचीत से निकालें हल

केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में बोली-दशकों से यही प्रथा

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर राज्यपाल विधेयकों पर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो राज्यों को कोर्ट की बजाय बातचीत से हल निकालना चाहिए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान अदालतें नहीं हो सकतीं। लोकतंत्र में संवाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे यहां दशकों से यही प्रथा रही है। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने गुरुवार को और राष्ट्रपति की तरफ से बिल को मंजूरी, रोक या रिजर्वेशन मामले की सुनवाई की। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी एस नरसिम्हा और ए एस चंदुरकर शामिल हैं। मेहता ने आगे कहा कि मान लीजिए कि राज्यपाल विधेयकों पर विचार नहीं कर रहे हैं, तो राजनीतिक समाधान हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। ऐसा हर जगह नहीं होता कि मुख्यमंत्री अदालत की ओर दौड़ पड़ते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बातचीत होती है, मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलते

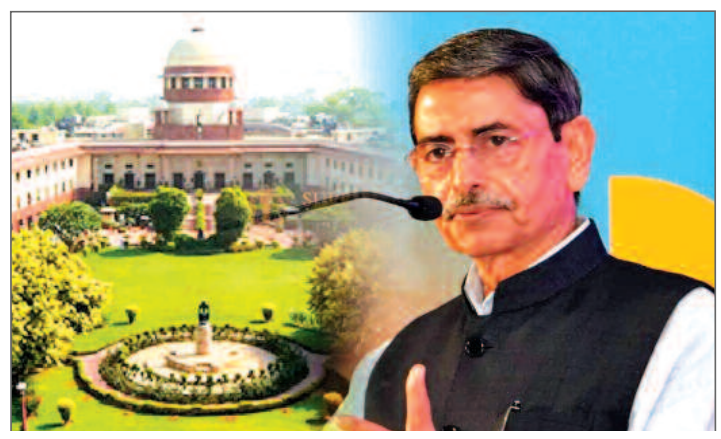

मिलते हैं और समाधान निकल आता है। कई बार फोन पर बातचीत से हल निकाला गया। तुषार मेहता ने आगे कहा कि दशकों से, विवादों को सुलझाने के लिए यही प्रथा अपनाई जाती रही है। प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल और राष्ट्रपति से मिलते हैं और कभी-कभी बीच का रास्ता निकल आता है। मेहता ने आगे तर्क दिया कि संविधान में कहीं भी राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने की कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है और जहां समय-सीमा दी गई है, वहां स्पष्ट रूप से संसद से विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल के लिए समय-सीमा तय करने वाला कानून बनाने का अनुरोध कर सकती है, लेकिन इस अदालत के फैसले के जरिए ऐसा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निर्वाचित सरकारें राज्यपालों की मर्जी पर नहीं चल सकतीं। अगर कोई बिल राज्य की विधानसभा से पास होकर दूसरी बार राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते। राज्यपाल के पास चार

अलग-अलग थाना क्षेत्र से पॉच अभियुक्त गिरफ्तार

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन द्वारा अपराध की रोकथाम एवं वांछित व वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अकराबाद पुलिस टीम ने तीन जुआरी यासीन पुत्र लाल मोहम्मद निवासी मोहल्ला शेखान कस्बा पिलखना थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़, गुलाम पुत्र एहसान खां निवासी मौहल्ला शेखान कस्बा पिलखना थाना अकराबाद जनपद अलीगढ व मेंहदी हसन पुत्र उमराव खां हाल निवासी मौहल्ला कोटियान कस्बा पिलखना थाना अकराबाद जनपद अलीगढ को 2860 रुपये फड़ व 52 ताश के पत्ते सहित जुआ खेलते हुए कस्बा पिलखना के डेरा मोहल्ले मे तालाब के पास खेत से गिरफ्तार किया। तो वहीं थाना गांधीपार्क पुलिस ने एक वारण्टी अभियुक्त योगेन्द्र पुत्र थान सिंह निवासी डोरी नगर थाना गांधीपार्क जनपद अलीगढ़ को डोरी नगर थाना गांधी पार्क से गिरफ्तार किया।

बाबू जी ने हम सभी का मार्गदर्शन किया है: चौधरी

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कल्याण सिंह ने प्रदेश के लिए काफी काम हुआ है। उन्होंने राम मंदिर में प्रमुख योगदान दिया है। बाबूजी कल्याण सिंह के दिखाए हुए राश्ते पर हमें राजवीर सिंह राजू भैया के साथ चलना है। बाबू जी में हम सभी का मार्गदर्शन किया है, उनका हमेशा स्मरण रहेगा। उन्होंने सपा पर हमला बोला, कहा-अखिलेश अब यूपी में बांटो और राज करो की नीति नहीं चलने वाली। बाबू जी पुण्यतिथि पर संकल्प लेते हैं कि सपा की साइकिल को उखाड़ कर सैफई भेज देंगे, 2027 में सपा को साफ करना है।

बाबूजी ने अपना पूरा जीवन सेवा को समर्पित किया: ब्रजेश पाठक

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बाबूजी ने अपना पूरा जीवन सेवा को समर्पित किया। शिक्षक्र से लेकर राज्यपाल तक अच्छा कार्य किया। राम मंदिर के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, वे पूरे देश के नेता थे। बाबूजी ने सनातन धर्म की पताका को सबसे ऊंचा फहराया है। बाबूजी ने अपनी सीएम की कुर्सी को छोड़कर राम मंदिर की ओर कूच किया था, आज यहां पर मौजूद जनता उनके प्रति सम्मान को दिखाता है।

शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग: उमा भारती

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि शाहजहांपुर का भी नाम बदला जाना चाहिए, अखिलेश यादव ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। अगर दिमाग गुलामी का हो तो क्या कहेगा। नाम की महिमा तब समझेगा जो राष्ट्रीय स्वाभिमान रखे। बाबूजी की जयंती पर याद है, 11 साल की उम्र में कल्याण सिंह जी से संपर्क हुआ, उन्होंने मंत्री बनते ही पत्र भेजा। उन्होंने कारसेवकों पर गोली नहीं चलाने का आदेश न देने की बात कही, क्योंकि वे राम भक्त थे।

कलराज मिश्र ने कल्याण सिंह को किया याद

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि कल्याण सिंह का नाम आते ही ऐसा लगता है कि वह हमारे पास बैठे हैं। उनसे गहरा सम्बन्ध है। भाजपा गठन के दौरान ही उनके साथ काम किया। 1980 में भाजपा स्थापना के बाद मैं, कल्याण सिंह और स्वर्गीय सूर्यकृष्ण तीनों महामंत्री थे। 1986 में कल्याण सिंह जी को यूपी भाजपा अध्यक्ष बनाना जरूरी माना गया, और मैं महामंत्री बना। पार्टी स्थापना में मैं भी था। हर विचार-विमर्श में तय किया गया पंचनिष्ठा राष्ट्रीयता, सर्वपन्थ समभाव, लोकतंत्र, समानता और नैतिक राजनीति। कल्याण सिंह ने कहा, क्यों न कर्मनिष्ठा भी घोषित करें। पांच नारे दिए-गांव, गरीब, किसान, झोपड़ी का इंसान, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का सम्मान, नौजवानों का उत्थान।

अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने में देरी न हो: केशव प्रसाद मौर्य

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर आयोजित हिंदू गौरव दिवस में कहा कि कल्याण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की बात कही और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। हिंदू गौरव दिवस में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबूजी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए।

पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल को स्टालिन ने बताया काला विधेयक

चेन्नई, एजेंसी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को 130वें संविधान संशोधन विधेयक को राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामले थोपने और उन्हें पदों से हटाने वाला काला विधेयक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 दिन की गिरफ्तारी का मतलब है बिना किसी मुकदमे या अदालती सजा के निर्वाचित मुख्यमंत्री को हटाना। हालांकि, यह भाजपा का एक फरमान मात्र है। तानाशाही इसी तरह शुरू होती है, वोट चुराओ, विरोधियों को चुप कराओ और राज्यों को कुचलो। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 में प्रधानमंत्री, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर अपराध के आरोपों में पद से हटाने का प्रावधान है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे और यह समिति अपनी रिपोर्ट अगले संसद सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक पेश करेगी। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने कहा, 130वां संविधान संशोधन कोई सुधार नहीं है - यह एक काला दिन है और यह एक काला विधेयक है। मैं इस विधेयक की कड़ी निंदा करता हूं, जो लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार करता है, और मैं सभी लोकतांत्रिक ताकतों से भारत को तानाशाही में बदलने के इस प्रयास के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करता हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री के तहत भारत को तानाशाही में

बदलकर संविधान और इसकी लोकतांत्रिक नींव को अपवित्र करने का फैसला किया है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि वोट चोरी के खुलासे के बाद, जिस जनादेश के आधार पर केंद्र में भाजपा सरकार बनी है, वही गंभीर सवालों के घेरे में है। द्रमुक प्रमुख ने कहा, इसकी (सरकार की) वैधता संदिग्ध है। धोखाधड़ी से जनादेश चुराने के बाद, भाजपा अब इस खुलासे से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश में है। इसके लिए, वे 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाए हैं। उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक संशोधन निश्चित रूप से अदालतों द्वारा रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि दोष का निर्णय केवल मुकदमे के बाद ही किया जाता है, न कि केवल मामला दर्ज होने से। स्टालिन ने कहा कि यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में क्षेत्रीय दलों को डराने का एक भयावह प्रयास है, जिनके नेता विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री या मंत्री हैं। इसकी मंशा है कि हमारे साथ रहो वरना...। द्रमुक प्रमुख ने कहा, किसी भी उभरते तानाशाह का पहला कदम अपने प्रतिद्वंद्वियों को गिरफ्तार करने और पद से हटाने की शक्ति खुद को देना होता है। यह विधेयक ठीक यही करने का प्रयास करता है। विरोध कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 'इंडिया' गठबंधन का एकमात्र संविधान भ्रष्टाचार ही है। स्टालिन को संबोधित करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि धन शोधन के आरोपों में गिरफ्तार किए गए मंत्री को बिना विभाग के मंत्री के रूप में बनाए रखने से ज्यादा स्याह या अपमानजनक कुछ नहीं है और उन्होंने द्रमुक शासन को बेशर्म सरकार करार दिया। अन्नामलाई ने कहा कि 'इंडिया' गठबंधन के एक अन्य भ्रष्टाचार योद्धा, अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने के बावजूद कई महीनों तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच लोकसभा में बुधवार को 'संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025', 'संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025' और 'जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025' पेश किए।

गुरुग्राम से नूंह तक अरावली में 10 हजार एकड़ में बनेगी जंगल सफारी

गुरुग्राम, एजेंसी।
हरियाणा सरकार ने अरावली क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी जंगल सफारी परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो राज्य को ईको-टूरिज्म के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करेगी। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने बुधवार को समीक्षा बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित यह परियोजना, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री मोदी के हाथों कराने की योजना है।

जंगल सफारी गुरुग्राम और नूंह जिलों में लगभग दस हजार एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैलेगी। पहले चरण में लगभग ढाई हजार एकड़ में काम शुरू होगा, जिसकी डिजाइनिंग और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) अगले दो महीनों में तैयार कर ली जाएगी। मंत्री ने बताया कि परियोजना के लिए ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी की जाएगी।

परियोजना पहले पर्यटन विभाग के अंतर्गत थी, लेकिन मुख्यमंत्री नायब

सिंह सैनी के निर्देश पर अब इसकी जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई है। मंत्री ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में नागपुर की गोरेवाड़ा सफारी और गुजरात की वनतारा परियोजना का दौरा कर प्रेरणा ली है। बैठक में लाइफ साइंस एजुकेशन ट्रस्ट ने एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना केंद्रीय जू प्राधिकरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियमों के अनुसार विकसित की जाएगी।

यह एक बड़े निवेश की योजना है और इसके संचालन के लिए पीपीपी मॉडल पर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जिस तरह गुजरात ने अपनी परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन किए हैं, उसी तरह हरियाणा में भी इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा।

रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे

राव नरबीर सिंह ने कहा कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना से स्वदेशी प्रजातियों का वनरोपण, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, भूजल का पुनर्भरण और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित होगा। इससे न केवल पर्यावरण को मजबूती मिलेगी।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के डॉक्टर सहित 8 ने किया सरेंडर, 30 लाख रुपये का था इनाम

नारायणपुर, एजेंसी।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। फोर्स के दबाव और मुठभेड़ में मारे जाने के डर से अबूझमाड़ इलाके में सक्रिय 8 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में डिवीजनल कमेटी सदस्य डॉ. सुकलाल और दो महिला नक्सली शामिल हैं। सभी ने नारायणपुर के एसपी रॉबिनसन गुड़िया के सामने सरेंडर किया है। इन नक्सलियों पर कुल 30 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

6 पुरुष और 2 महिलाओं ने किया सरेंडर: बता दें कि एक समय अबूझमाड़ को नक्सलियों की अघोषित राजधानी कहा जाता था, लेकिन फोर्स के बढ़ते प्रभाव और बीहड़ इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप खुलने से नक्सलियों में दहशत है। इंद्रावती एरिया कमेटी में नक्सलियों के डॉक्टर के नाम से चर्चित सुखलाल उर्फ़ मुकेश ने अपने 7 साथियों के साथ एसपी

के सामने कर दिया। 8 सक्रिय माओवादी में 6 पुरुष और 2 महिला शामिल हैं। इन नक्सलियों के सरेंडर करने से माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों पर सरकार ने कुल 30 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। सरेंडर करने वालों में इंद्रावती एरिया कमेटी का डॉक्टर सुखलाल ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटा है। नक्सलियों के डॉक्टर का सरेंडर माओवादी संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यह सरेंडर अभियान नक्सलियों के खोखले होते संगठन और विकास की ओर बढ़ते ग्रामीणों की सोच को दर्शाता है। नारायणपुर एसपी रॉबिनसन गुड़िया ने कहा कि लगातार विकास कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना, सरकारी योजनाओं का लाभ और सुरक्षा बलों के दबाव से नक्सली संगठन कमजोर हो रहा है। नियाद-नेल्लानार योजना ने विशेषकर अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों के नेटवर्क को कमजोर करने का काम किया है। सुखलाल के सरेंडर से नक्सली संगठन के चिकित्सा और इलाज व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। डॉक्टर सुखलाल नक्सलियों के बीच इलाज और मेडिकल सपोर्ट का प्रमुख जिम्मेदार माना जाता था।

यूपी में योगी सरकार शुरू करने जा रही बड़ा अभियान, डीएम को प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश

लखनउ, एजेंसी।
उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री को लेकर बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 16 सितम्बर, 2025 से प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिलाधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति पर प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग को निर्देश दिया गया है कि राजस्व अधिकारियों को मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) उपलब्ध कराई जाए, ताकि अधिकार अभिलेख में मालिकों के नाम को आधार के अनुसार सही किया जा सके।

प्रदेश में कुल 2.88 करोड़ से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया है। इसके सापेक्ष अब तक 50 प्रतिशत से अधिक लगभग 1.45 करोड़ किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। किसानों की फार्मर रजिस्ट्री में अब तक बिजनौर जिला सबसे आगे है, जहां 58प्रतिशत से अधिक रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद हरदोई (57.84प्रतिशत), श्रावस्ती (57.47प्रतिशत), पीलीभीत (56.89प्रतिशत) और रामपुर (56.72प्रतिशत) टॉप-5 जिलों में शामिल हैं। जो किसान अभी तक रजिस्ट्री का हिस्सा नहीं हैं, उनके डाटा का फील्ड ऑफिसर्स द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसमें अमरोहा, आजमगढ़, बलरामपुर, एटा और जौनपुर जैसे जिलों में 100 प्रतिशत वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है।

योगी सरकार ने जिलाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों का 100प्रतिशत पंजीकरण अगली किस्त जारी होने से पहले पूरा हो। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों को व्यापक आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियां चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को विशेष रूप से चेताया गया है कि पिछड़ रहे जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएं।

बेहतरीन और शानदार व्यवस्थाओं के साथ संपन्न हुआ कार्यक्रम

फोटो नं0 107

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷

पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि एवं तृतीय हिन्दू गौरव दिवस पर ताला नगरी में आयोजित कार्यक्रम

में नगर निगम अलीगढ़ ने बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास सभी को कराया।

कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ समेत अनेक वीवीआईपी जनप्रतिनिधियों का आगमन हुआ, जहाँ नगर निगम द्वारा किए गए इंतज़ाम ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक और भव्य रूप प्रदान किया।

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा स्वयं कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहकर पूरी व्यवस्थाओं की कमान संभाले रहे। पंडाल, हेलीपैड और पार्किंग क्षेत्र में दलदल व गड्ढों की स्थिति के बावजूद नगर निगम ने पिछले सात दिनों से लगातार जेसीबी मशीन, घास कटिंग, हाइवा टिपर, ट्रैक्टर, छोटे रोबोट, पाँच सीवर जेटिंग मशीन और एंटी-स्मोक गन संसाधनों को लगाकर स्थल को सुसज्जित और व्यवस्थित किया।

तो वही नगर निगम जलकल विभाग ने भव्य कार्यक्रम में आये हजारों लोगो को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई। कार्यक्रम के दिन नगर निगम की 35 अधिकारियों और 1050 सफाई कर्मियों की 80 टीमें सुबह से लेकर कार्यक्रम की समाप्ति तक मुश्तैदी से तैनात रहीं।

सभी टीमों ने स्वच्छता, यातायात एवं अन्य व्यवस्थाओं को बेहतरीन ढंग से सुनिश्चित किया। नगर आयुक्त ने मुख्यमंत्री के आगमन को गरिमामयी बनाने में नगर निगम अधिकारियों कर्मचारियों, प्रवर्तन दल, सफाई कर्मियों द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हुए उनकी पीठ थपथपाई और सभी को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में आयोजित हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के पीडीए कार्ड (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) पर तीखा हमला बोला।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये पार्टियां जातीयता का जहर फैला रही हैं और इसके लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी निशाना बना रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कोई न्यायाधीश सही फैसला देता है, तो उसे धमकाया जाता है, और अब तो चुनाव आयोग को भी धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ ये दल एसपीडीएए की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वे बांग्लादेशी घुसपैठियों, पाकिश्तानी और रोहिंग्याओं को मतदाता बनाकर भारत के वंचितों और पिछड़ों को मतदान से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब इस प्रक्रिया को रोकने के लिए काम किया जाता है, तो ये पार्टियां संसद की कार्यवाही में बाधा डालती हैं।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, उनकी

नीयत कभी भी सबका विकास की नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने सबका साथ तो लिया, लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवारों का किया। उनके शासनकाल में न तो व्यापारी और न ही बेटियां सुरक्षित थीं, जिसके कारण देश और प्रदेश पिछड़ते चले गए।

मुख्यमंत्री ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके 1990 के कार्यकाल को आज की भाजपा सरकार की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि आज जहां यह कार्यक्रम हो रहा है, वह ताला नगरी भी बाबूजी की स्मृतियों को ताजा करती है, क्योंकि उन्होंने ताला उद्योग को प्रोत्साहित कर रोजगार के साथ-साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को पूरा किया था, जो कि विकसित भारत का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि जब इन पार्टियों की सरकारें थीं, तो त्योहारों पर दंगों का साया पड़ जाता था, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टिकरण की नीति है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने को भाजपा के संकल्प को पूरा करने का उदाहरण बताया, जिससे आतंकवाद का खात्मा हुआ।

उन्होंने यह भी कहा कि पहले सिर्फ घोषणाएं होती थीं, लेकिन अब उनका मूर्त रूप देखने को मिल रहा है। पिछले साढ़े आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश दंगा-मुक्त हुआ है। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, सांसद साक्षी महाराज, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, पूर्व सांसद विनय कटियार, पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, पूर्व सांसद एवं कार्यक्रम आयोजक राजवीर सिंह राजू, प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी संबोधित किया।

दोस्ती के बाद शादी फिर पहचानने से मना करने लगा युवक

सोनभद्र, एजेंसी।
झारखंड की अनपरा थाना क्षेत्र की एक युवती की यूपी के सोनभद्र के एक युवक से फेसबुक से दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली और पति-पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ दिन के बाद युवती अपने मायके चली गई। मंगलवार की रात जब वह घर पहुंची तो युवक ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। युवती उसके दरवाजे पर धरने पर बैठ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को काफी समझाया, लेकिन युवती घर में जाने के लिए अड़ी रही।

जानकारी के अनुसार झारखंड के गढ़वा की रहने वाली एक युवती की चार साल पहले फेसबुक के जरिए एनसीएल ककरी परियोजना में कार्यरत शशि कुमार से मुलाकात हुई थी। दोस्ती जब प्यार में बदली तो दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। युवती ने बताया कि शादी के बाद वह शशि के साथ ककरी कॉलोनी के आवास में दस दिन तक पति-पत्नी की तरह रही। बाद में अपनी मां के कहने पर शाशि ने उसे मायके भेज दिया। आरोप है कि इसके बाद शशि ने अपना मोबाइल बंद कर लिया और संपर्क तोड़ दिया। सोमवार सुबह जब वह दोबारा ककरी कॉलोनी पहुंची तो शशि ने दरवाजा बंद कर लिया और उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इस पर युवती दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गई।

जयपुर नगर निगम हेरिटेज में भाजपा चेयरमैन-पार्षदों का अपनी ही पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप

जयपुर, एजेंसी।
जयपुर नगर निगम हेरिटेज इन दिनों सियासी घमासान का अखाड़ा बना हुआ है। बुधवार को माहौल उस वक्त और गरमा गया जब बीजेपी के चेयरमैन और पार्षदों ने अपनी ही पार्टी की नगर निगम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 20 से ज्यादा बीजेपी पार्षदों ने मेयर और कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाते हुए निगम मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान पार्षदों ने भ्रष्टाचार मुक्त निगम की मांग उठाते हुए भजन तक गाए और मेयर-कमिश्नर की सद्बुद्धि की दुआ मांगी।

बीजेपी पार्षद सुभाष व्यास ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा बोर्ड के कार्यकाल में बस्सी सीतारामपुरा की 100 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन गलत ढंग से पट्टों पर जारी कर दी गई। उन्होंने खुलकर कहा कि इस जमीन घोटाले में वही सभी लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने फाइल पर साइन किए। व्यास ने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई

की जाए। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि गलत तरीके से जारी किए गए पट्टों को तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए।

पार्षद सुभाष व्यास ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा ने साधारण सभा की बैठक में हर पार्षद के वार्ड में विकास कार्यों के लिए एक-एक करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। इन कामों को बाकायदा सैंक्शन भी किया गया था। लेकिन जैसे ही नए कमिश्नर निधि पटेल आईं, सभी विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, वार्डों की सफाई व्यवस्था के लिए जो कर्मचारी दिए गए थे, उन्हें भी हटा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि वार्डों की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई।

गुस्साए पार्षदों ने निगम मुख्यालय में डेरा डाल दिया और साफ कहा कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वे भूख हड़ताल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी चेयरमैन उत्तम शर्मा ने भी निगम प्रशासन पर करारा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सिविल लाइन जोन में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर फर्जी पट्टे जारी किए गए। शर्मा ने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जहां वार्डों के विकास कार्य ठप पड़े हैं, वहीं खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। धरने में चेयरमैन सुरेश नवरिया, उत्तम शर्मा, माणक शर्मा, संतोष कंवर, महेंद्र पहाड़ियां, हेमेंद्र शर्मा, बबीता तंवर, मनोज दुग्गल, अंशुल शर्मा, ज्योति चौहान, विक्रम सिंह, रवि सैनी, पार्षद सुभाष व्यास, राजेश कुमावत, मंजू राकेश बागड़ा, विमल अग्रवाल, सुनील दत्ता, श्याम सुंदर सैनी और राहुल शर्मा समेत बीजेपी के कई दिग्गज पार्षद मौजूद रहे।

धरना शुरू होते ही नगर निगम मुख्यालय सियासी रणभूमि में बदल गया। भाजपा पार्षदों के सुर तीखे थे और मेयर-कमिश्नर पर आरोप गंभीर। एक ओर भ्रष्टाचार के आरोपों की गूंज थी तो दूसरी तरफ ठप पड़े विकास कार्यों और चरमराई सफाई व्यवस्था पर सवाल। पार्षदों ने साफ कर दिया कि यह लड़ाई लंबी चलेगी और जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, वे पीछे नहीं हटेंगे।

बसपा अध्यक्ष मायावती पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने एक यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि बसपा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र मोहित ने बुधवार शाम शालीमार गार्डन थाने में यूट्यूबर पुनीतसुपरस्टार (मूल नाम प्रकाश कुमार) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में आरोप लगाये गये हैं कि यूट्यूबर ने सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' पर डाले गये एक वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी। पुलिस उपायुक्त निमिष पाटिल के मुताबिक प्राथमिकी में कहा गया है कि वायरल हुए इस वीडियो की वजह से बहुजन समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी यूट्यूबर के मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

निर्माणाधीन मकान से सामान चोरी

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷। नंदग्राम सी-ब्लॉक में रहने वाले फूल सिंह राठौर का कहना है कि उनका मकान साईं मंदिर वाली गली में है, जिसमें मरम्मत का काम चल रहा है। 19 अगश्त की दोपहर डेढ़ से दो बजे के बीच में अज्ञात चोर उनके घर से पानी की मोटर, ग्राइंडर मशीन, टाइस्ल कटिंग मशीन, हैमर गिल्टी मशीन तथा पीतल की दस टोंटियां चोरी करके ले गए। सामान गायब देख घटना का पता चला। फूल सिंह राठौर के मुताबिक उन्होंने काफी खोजबीन की, लेकिन सामान का कुछ पता नहीं चला जिसके बाद नंदग्राम थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। एसीपी नंदग्राम पूनम मिश्रा ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। चोरों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है।

छह लाख की पुरानी करेंसी के साथ झोलाछाप गिरफ्तार

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷। खोड़ा थाना पुलिस ने बुधवार देर रात छह लाख की पुरानी करेंसी के नोटों के साथ झोलाछाप को गिरफ्तार किया है। करेंसी करीब नौ साल पहले चलन से बाहर कर दी गई थी। पूछताछ कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। खोड़ा थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर बुधवार रात खोड़ा के लोकप्रिय विहार निवासी जयवीर सिंह के घर पर छापा मारा। वह चिकित्सक होने का दावा कर घर में ही पैथोलोजी लैब चलाता है। यहां से पुलिस ने एक-एक हजार के पुराने नोटों की छह गड्डियां बरामद की हैं। जयवीर मूलरूप से अलीगढ़ के टप्पल में आदमपुर गांव का रहने वाला है। उसका कहना था कि गांव का ही एक व्यक्ति देकर गया था। उसने कहा था कि किसी से 20 प्रतिशत कमीशन देकर करेंसी बदलने की बात हुई है। हालांकि पुलिस की जांच में आरोपी की बातों का अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी सालों से पुरानी करेंसी अपने पास रखे हुए था और बीते कुछ दिनों से इसे बदलने के लिए वह लोगों से बातचीत कर रहा था। इसी के चलते पुलिस को सूचना मिली और उसे दबोच लिया। सीओ इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवाश्तव ने बताया कि जयवीर को गिरफ्तार कर लिया है।

किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में भाई समेत नाबालिग को पकड़ा

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷। शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में नाबालिग और उसके भाई को पकड़ा है। नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह भेजकर आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। थानाक्षेत्र में रहने वाली किशोरी 22 जुलाई को लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने 15 अगश्त को पीड़िता को गाजियाबाद स्टेशन से बरामद किया था। पीड़िता ने बताया कि पास में रहने वाला किशोर बहलाकर उसे कानपुर ले गया था। यहां किशोर के भाई अर्जन निवासी फतेहपुर ने उससे दुष्कर्म किया। दोनों के चंगुल से छूटकर वह गाजियाबाद पहुंची। मंगलवार को पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया, जिससे पूछताछ के बाद अर्जुन को भी गिरफ्तार कर लिया।

ट्रेन में यात्रियों का सामान लूटने वाले को ढाई साल की सजा

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷। गिरोह बनाकर ट्रेन में यात्रियों का सामान लूटने वाले अभियुक्त को अदालत ने ढाई साल कैद की सजा सुनाई है। अदलात ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक, 23 अक्तूबर 2022 को जीआरपी ने सूरज, संतोष, विक्की और आशीष को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि सूरज साथियों के साथ गैंग बनाकर रेलवे स्टेशन और ट्रेन में यात्रियों के सामान की चोरी करता था। सभी अभियुक्तों पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। गैंग लीडर सूरज की फाइल को सहअभियुक्त से अलग कर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-12 के न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सूरज को गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलापों के आरोप में दो साल छह माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश जारी किए।

घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में चार पर केस दर्ज

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷। मोदीनगर के थानाक्षेत्र के गांव शाहजहांपुर में बुधवार रात को घर के बाहर गाली देने का विरोध करना एक युवक को काफी महंगा पड़ा। दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट कर तोड़फोड़ की। पुलिस ने चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गांव शाहजहांपुर निवासी नवीन कुमार ने बताया कि बुधवार रात को घर के बाहर कुछ युवक गाली दे रहे थे। नवीन ने गाली देने से मना किया तो विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट कर तोड़फोड़ की। पीड़ति की तहरीर पर पुलिस ने हेमंत,मुकेश,सत्यम व शीतल निवासी गांव शाहजहांपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है।

प्रधान राहिल परवीन की मौत के मामले में पुलिस को दी हत्या की तहरीर

✷ एनसीआर टुडे. स्योहारा ✷

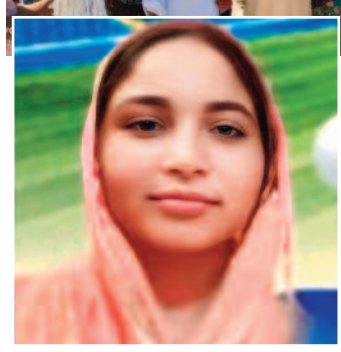

स्योहारा क्षेत्र के ग्राम मेवा नवादा की मौजूदा ग्राम प्रधान राहिल परवीन की मौत को लेकर गांव में फैली सनसनी मृतका के भाई ने थाना में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उनकी बहन की हत्या दहेज व आपसी विवाद के चलते की गई है और उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार व बुधवार की रात्रि में थाना क्षेत्र के ग्राम मेवा नवादा की मौजूदा ग्राम प्रधान राहिल परवीन उम्र करीब 35 वर्ष पत्नी इशरत अली उसी के घर में गले में दुपट्टा फंदा लगा हुआ मिला और खिड़की में बंधा हुआ घुटनों के बल शव रखा हुआ पाया गया जिससे गांव में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी इसकी सूचना मृतक प्रधान राहिल परवीन के परिजनों को दी गई।

मृतका के भाई महराजुद्दीन निवासी ग्राम ढांकी थाना शिवाला कला ने आकर स्योहारा थाना हाजा में तहरीर देकर बताया कि उनकी बहन राहिल परवीन उम्र करीब 35 वर्ष का विवाह लगभग दस 10 वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार इशरत अली पुत्र दीन मोहम्मद निवासी ग्राम मेवा नवादा से हुआ था विवाह के समय परिजनों ने अपनी हैसियत अनुसार दहेज भी दिया था।

आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष राहिल परवीन से असंतुष्ट रहता था और आए दिन उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था आगे बताया है की इशरत पहले भी राहिल को प्रताड़ित कर जान से मारने की कोशिश कर चुका है जिसकी जानकारी उसने फोन पर परिजनों को दी थी उस समय पंचायत में मामला निपटाया गया और इशरत अली व उसके परिवार ने दोबारा गलती न करने का भरोसा दिया था।

महराजुद्दीन ने तहरीर में आरोप लगाया कि 19 अगश्त 2025 की रात लगभग 10 बजे उनकी बहन राहिल परवीन ने अपनी छोटी बहन रुबीना को फोन कर बताया कि इशरत अली सहित कुछ लोग उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं फोन पर जिन लोगों के नाम लिए गए वे हैं।

इशरत अली पुत्र दीन मोहम्मद हारून उर्फ लगंडा पुत्र अनवार दानिश पुत्र इस्लामुद्दीन राशिद डीलर फर्सत पुष्पेंद्र पुत्र बलवीर वाहजबीन पुत्र अहसान साथ ही दो अन्य अज्ञात व्यक्ति परिजनों का आरोप है कि इन्हीं लोगों ने राहिल परवीन की हत्या कर उसे दुपट्टे से गले में फंदा लगाकर खिड़की से लटका दिया।

ताकि मामला आत्महत्या का लगे सूचना मिलने पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी धामपुर स्योहारा थाना प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह सहसपुर चौकी प्रभारी यश देव शर्मा फॉरेंसिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और डेड बॉडी का पंचनामा भर कर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी परिजनों का कहना है कि आरोपी दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं तथा राजनीतिक पकड़ के चलते मामले को रफा-दफा करने की कोशिश कर रहे हैं।

परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है पुलिस का कहना है कि इस घटना की जांच की जा रही है और अभी कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा मित्रों ने बीएलओ ड्यूटी संबंधी समस्याओं पर सौंपा ज्ञापन

✷ एनसीआर टुडे. किरतपुर ✷

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ब्लॉक किरतपुर की ब्लॉक कार्यकारिणी ने गुरुवार को खंड शिक्षा अधिकारी किरतपुर को शिक्षा मित्रों की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि ब्लॉक किरतपुर में पंचायत चुनाव के दौरान अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी हटाकर शिक्षा मित्रों की BLO ड्यूटी लगाई जा रही है, जबकि अधिकांश शिक्षा मित्र विधानसभा श्तर पर पहले से ही BLO के रूप में कार्यरत हैं।

ऐसे में एक साथ दोनों स्थानों पर कार्य करना संभव नहीं है। संघ ने यह भी आपत्ति जताई कि कुछ दिव्यांग शिक्षा मित्रों की भी BLO ड्यूटी लगाई गई है, जो नियमों के विरुद्ध है। साथ ही कई शिक्षा मित्रों की ड्यूटी उसी पंचायत में लगाई गई है, जहाँ वे स्वयं निवासी हैं। इस कारण आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति बन सकती है।

संघ ने चेतावनी दी कि यदि इन समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो शिक्षा मित्र धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।

इस अवसर पर अंजिता, दिग्विजय, गजेंद्र, नीरज, अनिल वालियान, मोहसिना, अंजू, प्रियंका आदि मौजूद रहे।

ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद कुमार नरवाल, महामंत्री अरुण कुमार तथा महिला प्रकोष्ठ की महामंत्री नीतू सिंह शामिल रहीं।

भगवान कृष्ण की छठी पर भंडारे का आयोजन किया गया

✷ एनसीआर टुडे. नगीना ✷

नगीना क्षेत्र के ग्राम कालाखेड़ी में प्राचीन शिव मंदिर पश्चिम वाले में भगवान कृष्ण का छठी पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया।

भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। शिव मंदिर के प्रांगण में गुरुवार को भगवान कृष्ण की छठी मनाई गई। इस मौके पंडित विनीत कुमार शर्मा द्वारा हवन पूजन किया गया। भगवान कृष्ण की छठी में मुख्य यजवान संदीप कुमार चौहान के कर कमलो द्वारा हवन का कार्य किया गया।

हवन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। भण्डारे में विशेष सहयोग संदीप कुमार चौहान व भूपेंद्र सिंह चौहान का रहा।

कालाखेड़ी ग्राम की कीर्तन कमेटी के लोगों ने व अन्य लोगो ने तथा आसपास क्षेत्रों के लोगो ने मंदिर में पहुँचकर .भगवान कृष्ण की छठी में भाग लिया। समर्थ के अनुसार सहयोग भी प्रदान किया।

इस मौके पर विभिन्न श्रद्धालु उपस्थित रहे नारायण सिंह चौहान, गजेंद्र सिंह चौहान, देवराज सिंह चक्की वाले राहुल कुमार एडवोकेट जयप्रकाश सिंह उर्फ पप्पू महेश कुमार उर्फ सेठी धर्मवीर सिंह चौहान संजय कुमार चौहान राजवीर सिंह मुंशी राजकुमार सिंह चौहान महेश कुमार राजवीर सिंह एडवोकेट हेमराज सिंह पूर्व डायरेक्टर साहब गन्ना सोसाइटी विवेक चौहान लोकश कुमार चौहान पंडित अनिल कुमार शर्मापंडित विनोद कुमार शर्मा लक्ष्य शर्मा जयपाल मुंशी पूर्व प्रधान नरेश कुमार चौहान ज्ञानेंद्र कुमार मुंशी ब्रजराज सिंह चौहान चौधरी योगेश कुमार हरगांव वालेआदि गढ़ मान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

पचास हजार रुपये रिश्वत लेते कलछीना चौकी प्रभारी गिरफ्तार

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

मोदीनगर में एंटी करप्शन मेरठ यूनिट की टीम ने गुरुवार को कलछीना पुलिस चौकी प्रभारी को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया।

मोदीनगर थाने में दरोगा के खिलाफ केस दर्ज कर रकम सील कर दी गई है। आरोपी को निलंबित कर दिया गया है। कलछीना निवासी इनामूल हक ने बताया कि 30 अगश्त 2024 को गांव निवासी रिजवान ने महिला ताहिरा को अपनी दुकान बेंची थी। बैनामा में इनामूल हक गवाह बन गए। दिसंबर में रिजवान के पिता जान मोहम्मद ने भोजपुर थाने में धोखे से दुकान बेचने की बात कहकर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। इसमें इनामूल का भी नाम था।

मामले की विवेचना कलछीना चौकी प्रभारी राजीव कुमार के पास थी। इनामूल का आरोप है कि चौकी प्रभारी ने 15 दिन पहले चार्जशीट से नाम हटवाने के नाम पर 75 हजार रुपये की मांग की थी। काफी परेशान होने के बाद जब बात नहीं बनी तो इनामूल ने रिश्वत मांगने की शिकायत मेरठ यूनिट की एंटी करप्शन विभाग में कर दी। इसके बाद एंटी करप्शन के प्रभारी दुर्गेश कुमार, राहुल देव और कृष्णपाल सिंह के नेतृत्व में 19 सदस्यीय टीम बनाई गई। गुरुवार को टीम कलछीना पहुंची और इनामूल को केमिकल लगे नोटो की गड्डी दे दी। जैसे ही इनामूल ने चौकी परिसर में दरोगा को गड्डी थमाई, टीम ने उसे दबोच लिया।

इसके बाद दरोगा के हाथ पानी के जग में डलवाए तो रंग लाल हो गया। इसके बाद टीम दरोगा को लेकर मोदीनगर थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। दरोगा जेल भेजने की दे रहा था धमकी इनामुल ने बताया कि रकम नहीं देने पर तो आरोपी दरोगा ने पुलिस टीम के साथ कई बार उसके घर पर दबिश दी, जबकि केस में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था।

दरोगा लगातार रकम देने के दबाव बना रहा था और नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी भी दे रहा था। वर्ष 2017 में ही बना था दरोगा दरोगा राजीव कुमार मूलरूप रूप से जिला मैनापुरी का रहने वाला है।

राजीव कुमार वर्ष 1997 में पुलिस विभाग में सिपाही पद पर भर्ती हुआ था। सन 2017 में ही यह प्रमोट होकर दरोगा बना था। दो महीने पहले ही कलछीना चौकी प्रभारी बनाया गया था।

नए टाउनशिप के लिए जमीन की बाधा एक माह में दूर होगी

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

नई टाउनशिप के लिए जमीन की बाधा एक माह में दूर करने की तैयारी है। इसको लेकर जीडीए किसानों से सहमति बनाने में जुटा है। हालांकि किसानों से सहमति नहीं बनने पर प्राधिकरण इसे अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है, जिसका प्रश्ताव 27 अगश्त को होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जा सकता है।

जीडीए राजनगर एक्सटेंशन के पास हरनंदीपुरम टाउनशिप विकसित करने में जुटा है। राजनगर एक्सटेंशन के पास मुख्यमंत्री शहरी विश्तारीकरण योजना के तहत नई टाउनशिप हरनंदीपुरम योजना बनेगी। पहले चरण में पांच गांव की करीब 350 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बसाने की योजना है। पिछले दिनों हुई बोर्ड बैठक में सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा दर पर जमीन खरीदने के प्रश्ताव को मंजूरी मिली थी।

फिर जीडीए ने किसानों से सहमति बनाना शुरू किया, जिसके तहत प्राधिकरण ने किसानों से पांच हेक्टेयर से अधिक जमीन का बैनामा भी अपने नाम करा लिया। वहीं, शेष बचे हुए किसानों से सहमति बनाने में लगा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि कई किसान अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

ऐसे में वह अपनी जमीन देने तक को तैयार नहीं है। अब प्राधिकरण इसका विचार कर रहा है कि यदि किसानों से सहमति नहीं बनती है, तो इस जमीन का अधिग्रहण किया जाए। इसका प्रश्ताव भी तैयार किया जा रहा है, ताकि ये प्रश्ताव 27 अगश्त को होने वाली बोर्ड बैठक में रखकर मंजूरी दिलाई जा सके। यदि बोर्ड इस प्रश्ताव को मंजूरी दे देगा, तो प्राधिकरण जमीन का अधिग्रहण सकता है।

हालांकि इसको लेकर सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि अधिग्रहण में दिए जाने वाले मुआवजे के विरोध में किसान कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, जिससे मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में भी फंस सकता है। 336 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा जीडीए हरनंदीपुरम योजना के लिए जीडीए पांच गांव की कुल 336.8444 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा। ये जमीन वहां के सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा दर पर खरीदी जा रही है, जिसमें नगला फिरोज मोहनपुर गांव की सबसे अधिक 192.6514 हेक्टेयर जमीन 7,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदी जाएगी।

इसके अलावा मथुरापुर गांव की करीब 14 हेक्टेयर, शमशेर गांव की करीब 86 हेक्टेयर, चम्पतनगर गांव की करीब 33 हेक्टेयर, भनेड़ाखुर्द गांव की करीब नौ हेक्येटर जमीन खरीदनी है। जमीन खरीदने पर 1200 करोड़ खर्च होंगे जीडीए अधिकारी बताते हैं कि प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष में हरनंदीपुरम योजना के लिए जमीन खरीदने पर 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

इसमें 400 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री शहरी विश्तारीकरण योजना के तहत शासन ने प्राधिकरण को भेजे थे। जबकि 800 करोड़ रुपये जीडीए खर्च करेगा। इस रकम से जमीन खरीदी जाएगी। इसके बाद 2026-27 वित्तीय वर्ष में फिर शासन श्तर पर फंड मिलेगा। साथ ही प्राधिकरण भी योजना के लिए बजट जारी करेगा। जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि हरनंदीपुरम के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में किसानों से सहमति बनाई जा रही है। यदि जरूरत पड़ी तो जमीन अधिग्रहण का प्रश्ताव बोर्ड बैठक में रखकर मंजूरी दिलाई जाएगी।

दूषित और बिना नंबर प्लेट वाले 436 वाहनों के चालान काटे

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस का अभियान जारी है। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वालों और बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया।

इस दौरान 436 वाहनों के चालान काटे गए और 11 वाहनों को सीज किया गया।

ट्रैफिक अधिकारी सच्चिदानंद ने बताया कि गुरुवार को यातायात पुलिस ने बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ और बिना नंबर प्लेट के वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। एसीपी की निगरानी में तीनों जोन में यातायात निरीक्षकों और उप निरीक्षकों ने यह अभियान चलाया।

ट्रैफिक पुलिस ने शहर, देहात के प्रमुख मार्गों, चौराहों तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन चेकिंग की। अभियान में विशेष रूप से पहचान छिपाने के उद्देश्य से नंबर प्लेट मानक के अनुरूप न रखने वाले, बिना नंबर प्लेट, जानबूझकर नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले वाहनों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 436 वाहनों का चालान किया गया और 11 वाहनों को सीज किया गया।

अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग कार्रवाई से बचने के लिए खुद को पुलिसकर्मी का परिजन या नेता का भाई बताया और फोन पर बात भी कराई, लेकिन किसी की सिफारिश काम नहीं आई।

प्रतिनिधि बन युवक के खाते से उड़ाए सवा लाख

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

खोड़ा थानाक्षेत्र में रहने वाली युवती से जालसाजों ने ग्राहक प्रतिनिधि बन सवा लाख रुपये ठग लिए। पीड़िता ने रैपिडो चालक की शिकायत के लिए इंटरनेट से मिले कंपनी के नंबर पर कॉल की थी, जिसके बाद झांसे में लेकर ठगी की गई। खोड़ा कॉलोनी में रहने वाली उमरा अंसारी निजी कंपनी में कार्यरत हैं।

उन्होंने पुलिस को बताया कि आठ अगश्त को वह दिल्ली के राजघाट से घर रैपिडो कैब बुक कर आई थीं। घर पहुंचने पर चालक ने बुकिंग की रकम से ज्यादा रुपये मांगे। इसकी शिकायत करने के लिए उन्होंने ग्राहक प्रतिनिधि के इंटरनेट से मिले नंबर पर काल की।

यह नंबर जालसाज का था, जिसने उमरा को लिंक भेजकर मोबाइल में हैकिंग एप इंस्टाल करा दिया और फिर चार बार में यूपीआई के जरिये सवा लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर कर लिए।

रोडरेज में फैक्टरी संचालक पर हमला करने वालों पर केस

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

काजीपुरा अंडरपास के नजदीक मंगलवार रात रोडरेज में फैक्टरी संचालक पर धारदार हथियार से हमले के मामले में कविनगर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों पर केस दर्ज कर लिया है।

घटना के संबंध में घायल के चचेरे भाई ने शिकायत दी थी। पुलिस आरोपियों को ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। डासना निवासी आसिफ एनएच-नौ के किनारे उद्योगकुंज औद्योगिक क्षेत्र में बैटरी गलाने की फैक्टरी चलाते हैं। मंगलवार रात करीब सवा 10 बजे वह कार से घर लौट रहे थे। एनएच-नौ किनारे काजीपुरा अंडरपास के नजदीक पहुंचने पर अन्य कार ने उनकी कार में टक्कर मार दी।

आसिफ अपनी गाड़ी में हुए नुकसान को देखने लगे तो दूसरी कार से उतपे चार लोगों ने उन पर धारदार हथियार और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में सिर फट गया आसिफ बुरी तरह लहूलुहान हो गए। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए।

परिजनों द्वारा आसिफ को मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं, केस दर्ज करने को लेकर वेव सिटी और कविनगर थाना पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही, लेकिन उच्चाधिकारियों के हश्तक्षेप पर कविनगर पुलिस ने केस दर्ज किया।

सीओ कविनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि आसिफ के चचेरे भाई अब्दुल मलिक की शिकायत के आधार पर चार अज्ञात कार सवारों के खिलाफ सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाने, संपत्ति को नुकसान व स्वेच्छा से चोट पहुंचाने तथा जानबूझकर अपमान करने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।

शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर साढ़े चार लाख ठगे

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

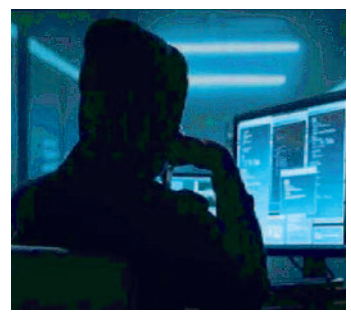

मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 4.60 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है।

पीड़ित के मुताबिक पूर्व परिचित ने धोखाधड़ी को अंजाम दिया। घटना के संबंध में पीड़ित ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कराया है। स्वर्ण जयंतीपुरन निवासी अश्वनी कुमार का कहना है कि परिचित के माध्यम से उनकी पहचान रिंकश मिश्रा नामक व्यक्ति से हुई थी। आरोपी ने उन्हें हाइटेक सॉफ्टनेयर और जेरोधा ऐप के जरिये निवेश पर मोटी कमाई का लालच दिया।

रिंकश मिश्रा ने विश्वास दिलाने के लिए अपना एक चेक भी दिया। भरोसा जमने पर उन्होंने पत्नी मुनमुन सिंह के नाम पर एक्सिस बैंक में खाता खुलवाकर 4.60 लाख रुपये आरोपी के कहने पर निवेश कर दिए। कुछ समय बाद जब पीड़ित ने हिसाब मांगा तो पता चला कि आरोपी परिवार सहित किराए का मकान छोड़कर फरार हो गया है।

आरोपी ने अपनी बेटी का नाम भी स्कूल से कटवा दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनके आधार कार्ड और मोबाइल सिम का दुरुपयोग कर उसे अपने नाम पर पोर्ट करा लिया।

रिंकश मिश्रा का कहना है कि उन्होंने डायल-112, जनसुनवाई पोर्टल, पुलिस आयुक्त कार्यालय और मधुबन बापूधाम थाने में कई बार प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक-हारकर उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।

सीओ कविनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर 21 अगश्त को आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

सड़क हादसों में भाई-बहन समेत चार घायल

एनसीआर टुडे. गाजियाबाद। अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में स्कूटी सवार भाई-बहन समेत चार लोग घायल हो गए तो वाहन भी क्षतिग्रश्त हो गए। पीड़ितों ने घटना के संबंध में थाने पर शिकायत दी। पुलिस का कहना है कि चालकों के खिलाफ केस दर्ज कर उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई की जा रही है। सिकरोड़ गांव में रहने वाले शुभम राय का कहना है कि 20 अगश्त को वह अपनी बहन दिव्या राय के साथ स्कूटी से कचहरी स्थित अपने चैंबर पर जा रहे थे। सुबह करीब साढ़े नौ बजे जैसे ही वह आरकेजीआईटी कॉलेज के पास पहुंचे तो काले रंग की बुलेट ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें तो हल्की चोटें आईं, लेकिन बहन दिव्या राय को पैर, कोहनी और टखने पर गंभीर चोट आईं। दुर्घटना के बाद आरोपी बुलेट चालक ने दबंगई दिखाते हुए मारपीट की और धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी बुलेट चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

बिजनौर में बड़ा खुलासा : झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध नर्सिंग होम से हर महीने करोड़ों की वसूली!

✷ एनसीआर टुडे. बिजनौर ✷

जनपद में झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध नर्सिंग होम का साम्राज्य खत्म होने के बजाय और फल-फूल रहा है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी "चेकिंग" के नाम पर प्रतिमाह आठ से दस लाख रुपए तक की अवैध वसूली कर रहे हैं।

सवाल उठता है कि जब भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, तो बिजनौर में यह गोरखधंधा कैसे चल रहा है?

क्या जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसर इन शिकायतों से अनजान हैं या फिर जानकर भी चुप्पी साधे हुए हैं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कड़े तेवर का असर जिले तक नहीं पहुँच रहा?

मीडिया कई बार इन काले कारनामों को उजागर कर चुका है। शिकायतें सीधे जिलाधिकारी और लखनऊ स्थित महानिदेशक तक पहुँच चुकी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई।

संपादकीय

यह सुधार नहीं करेक्शन है

जीएसटी ने इसके साथ मिलकर छोटे उद्यमियों की कमर तोड़ दी क्योंकि उनके लिए इस व्यवस्था के लिए जरूरी तकनीकी ज्ञान वाला एकाउंटेंट रखना संभव हुआ न क्रेडिट सिस्टम के अपने अदानों के खर्च के आधार पर कर माफी का आवेदन करना। इस क्रेडिट और कर वसूली के हिसाब को साथ पेश करके रिफंड मांगना और भी जटिल पहेली है।

लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी दरों में कमी की तैयारी वाली घोषणा के बाद से बाजार उछल रहा है, कंपनियां मन ही मन मलाई खाने लगी हैं, अर्थशास्त्री इसे आर्थिक सुधार का रुका हुआ फैसला या दूसरी खेप बताने लगे है और अर्थव्यवस्था को होने वाले 'लाभ' को लेकर तरह-तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं।

आधिकारिक बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि 20 और 21 तारीख को होने वाली राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन बदलावों की घोषणा कर दें। वैसे प्रधानमंत्री की घोषणा के तत्काल बाद ही यह खबर भी आ गई कि आम तौर पर 12 फीसदी रेट घटकर 5 फीसदी और 28 फीसदी वाले रेट कम करके 18 फीसदी कर दिया जाएगा। इसके बाद छोटी कारों फ्रिज, टीवी वगैरह के सस्ते होने के अनुमान मोटे-मोटे अक्षरों में बताए जाने लगे कि कारों के 75 हजार सस्ता होने का अनुमान है तो दीपावली के अवसर के लिए स्टाक बढ़ाने की खबर भी स्वाभाविक है। बाजार और आम लोगों में स्वागत का माहौल होना स्वाभाविक है। लंबी चर्चा और मतभेदों के चलते रुके पड़े जीएसटी का फैसला शुरू से विवादों में रहा है। बहुत तरह के उत्पाद करों और वैट की जगह जीएसटी लगाए जाने के मोदी सरकार के फैसले के बाद से ही उस पर कईतरह की आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं और उसे लेकर तकलीफ की शिकायतें भी आम रही हैं। किस चीज पर कर बढ़ा किस पर घटा यह लिस्ट तो बहुत बड़ी है लेकिन पाठ्यपुस्तकों समेत कुछ ऐसी चीजों को पहली बार कर के दायरे में लिया गया जिसे अभी तक कभी कर वसूलने की चीज नहीं माना गया था। यह भी मुद्दा है कि वही चीज खुले में, डिब्बे में या टेबल पर सर्व होने के साथ-साथ तीन-तीन दर पर टैक्स वसूलने का माध्यम बनी।

होटल में खाने पर सर्विस टैक्स है या नहीं यह आज तक विवाद का विषय ही रही। फिर भी मामले लोकल टैक्स के लिए छोड़ दिये गये हैं से भी एक रेट पर देश भर में कर वसूली की बात हवाई ही रही। और यह मात्र संयोग है कि जब जीएसटी का फैसला हुआ था उसे आसपास प्रधानमंत्री ने नोटबंदी लाकर पूरी अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया था। मोटा अनुमान है कि उससे हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई-करीब दो फीसदी की। जीएसटी ने इसके साथ मिलकर छोटे उद्यमियों की कमर तोड़ दी क्योंकि उनके लिए इस व्यवस्था के लिए जरूरी तकनीकी ज्ञान वाला एकाउंटेंट रखना संभव हुआ न क्रेडिट सिस्टम के अपने अदानों के खर्च के आधार पर कर माफी का आवेदन करना। इस क्रेडिट और कर वसूली के हिसाब को साथ पेश करके रिफंड मांगना और भी जटिल पहेली है और आंकड़ों का 'मिसमैच' जहां व्यवसायी का पैसा उलझा देता है, कर विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आमदनी का अवसर बन जाता है।

ये मामले कितनी बड़ी संख्या में हैं और कितनी बड़ी मात्रा में रिफंड जाता है यह हिसाब किसी को भी चकरा देगा। लेकिन असल में यह इस कर प्रणाली में मौजूद दोष को ही बताता है। जिस पैसे को बाद में लौटाना है वह वसूला ही क्यों जाए? और यह बात आसानी से कही जा सकती है कि सरकारी फैसला कर में कमी का होना, इसमें कमी का होना। सरकार पूरी प्रक्रिया पर पुनर्विचार नहीं कर रही है, कोई रुका हुआ सुधार नहीं आने वाला है। यह मात्र एक करेक्शन है।

कल के सुपर दोस्त और आज के दुश्मन नंबर एक ट्रम्प महाराज के फैसलों ने इसकी जरूरत बनाई है और सरकार ने भी जल्दी से हां किया है क्योंकि इस करेक्शन की जरूरत बढ़ गई है। ट्रम्प के फैसलों से पूरा आर्थिक माहौल भारी उदासी और अनिश्चितता से भर गया है। बाजार के जानकारों का मानना है कि अगर अभी घोषित सारे रेट उसी तरह लागू हुए तो जीएसटी वसूली में 8.6 फीसदी की कमी आएगी।

जो केंद्र और राज्यों के राजस्व का मात्र 0.25 फीसदी ही रहेगा और अगले वित्त वर्ष में यह 0.12 फीसदी फी रहेगा। अगर करखनिया उत्पादन और सेवा क्षेत्र ने कर घटाने से अपने कामकाज में सुधार किया तो यह कमी भी खत्म हो जाएगी और सरकार कर वसूली की परेशानियों या कर ढांचे के स्वरूप में बदलाव इसलिए नहीं करेगी क्योंकि जीएसटी ने हर छोटे बड़े व्यवसायी और सेवादार को इनफारमल सेक्टर से निकालकर फार्मल सेक्टर में ला दिया है और सूचना तकनीक के नेटवर्क की निरंतर निगरानी में पहुंचा दिया है। इससे टैक्स सर्विलांस बढ़ा है और सरकार की कमाई भी बढ़ते हुए लगभग 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गई है।

इस निगरानी से सिर्फ जीएसटी का लाभ नहीं है, इससे पीएफ खातों का हिसाब बढ़ा है और बिना नौकरियां या रोजगार दिए मजदूरों की संख्या बढ़ाने का दावा होने लगा है। उत्पादन के आंकड़ों में भी फर्क आया है क्योंकि वहां भी खरीद-बिक्री और क्रेडिट पॉइंट के आधार पर कर राहत का खेल कई तरह से चलता है।

अभी तक किसी भी शतर पर यह चर्चा नहीं है कि सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी की सामान्य सूची में ला देगी जबकि यह बात शुरू से कही जाती रही है। हम जानते हैं कि जब से यह व्यवस्था बनी है सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को बाहर रखकर हर साल दो ढाई लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर वसूल रही है और कभी कीमत घटाने पर लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाता। पेट्रोल के बड़े व्यापारी मालामाल हुए हैं या सरकार। पर इस बार यह चर्चा है कि सरकार आनलाइन गेमिंग को 40 फीसदी कर वाले सुपर ग्रुप में लाकर मोटा राजस्व वसूलेगी।

इसका धंधा बहुत तेज हुआ है (एक साल में लगभग छह गुना वृद्धि है) और आनलाइन सट्टेबाजी कराने में सरकार के लिए कोई नैतिक संकट नहीं है। इसी तरह बड़ी कारों और एसयूवी वाहनों की बढ़ती मांग भी उसके खजाने को भरने के लिए काफी हैं। सिगरेट, तंबाकू और गुटका पर ज्यादा कर का तर्क समझा जा सकता है लेकिन पेट्रोल-डीजल को जीएसटी से बाहर रखना, सट्टेबाजी को बढ़ावा देकर खजाना भरना सामान्य तर्क से बाहर है। और फिर भी कोई इसे रिफ़ार्म कहे तो यह बात हजम नहीं होती।

महामहिम की जबावदेही से आदिवासी क्षेत्रों को नई ताकत

सुधीर पाल

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार इस बात को लेकर मोर्चा खोले हुए है कि जब संविधान राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्णय लेने की समय सीमा में नहीं बांधे हुए है तो कोर्ट क्यों निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों और राष्ट्रपति के पास लंबित पड़े विधेयकों पर समय-सीमा तय करने का ऐतिहासिक फैसला दिया है, तो सवाल केवल विधेयक मंजूरी की देरी का नहीं है।

प्रश्न यह है कि पाँचवीं और छठी अनुसूची जैसे विशेष संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद पिछले सात दशकों में राज्यपालों और राष्ट्रपति- दोनों ने ही इन संवैधानिक दायित्वों का पालन शायद ही कभी गंभीरता से किया। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला केवल सामान्य केंद्र-राज्य विवादों तक सीमित नहीं है, बल्कि पंचम और षष्ठम अनुसूची के क्षेत्रों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और अधिकारों से भी गहराई से जुड़ा है। बहस इस पर नहीं है कि लोकतंत्र के संरक्षक के तौर पर राज्यपाल और राष्ट्रपति ने अपनी भूमिका नहीं निभाई है और इन्हें कैसे जबावदह बनाया जाए।

संविधान सभा में जब पाँचवीं और छठी अनुसूची पर चर्चा हो रही थी, तब आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा ने साफ़ कहा थाः

"आदिवासी समाज हजारों वर्षों से अपनी ग्रामसभाओं और पारंपरिक शासन व्यवस्था से चलता आया है। यह केवल प्रशासनिक संरचना नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। यदि संविधान इन परंपराओं को मान्यता नहीं देगा, तो आदिवासी समाज अपने को ठगा हुआ महसूस करेगा।" इसी बहस के दौरान डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी स्पष्ट किया था कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका केवल औपचारिक नहीं होगी, बल्कि वह संरक्षक की तरह कार्य करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि संविधान की यह दृष्टि कभी व्यवहार में नहीं उतरी। राज्यपाल राजनीतिक संतुलन साधने में उलझे रहे और राष्ट्रपति ने भी स्वतंत्र रिपोर्टों को नजरअंदाज कर दिया।

आदिवासी इलाकों में राज्यपालों की निष्क्रियता

पंचम अनुसूची विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय समुदायों के प्रशासन से संबंधित है। इसके अंतर्गत, अनुच्छेद 244(1) स्पष्ट करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का शासन विशेष प्रावधानों के अधीन होगा। राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है कि वह इन क्षेत्रों में लागू होने वाले किसी भी राज्य विधान को, चाहे पारित हो चुका हो, अस्वीकार, संशोधित या निलंबित कर सकता है। राज्यपाल पर यह संवैधानिक दायित्व डाला गया है कि वह समय-समय पर राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्ट भेजें।

परंतु वाशतविकता यह है कि संविधान लागू होने के बाद से बार-बार रिपोर्टें समय पर और निष्पक्ष रूप में राष्ट्रपति को भेजे जाने का एक भी ठोस उदाहरण सामने नहीं आता। राज्यपालों ने इस शक्ति का उपयोग आदिवासियों के पक्ष में नीति-निर्माण को प्रभावित करने के लिए लगभग कभी नहीं किया।

राज्यपाल के वार्षिक प्रतिवेदन का मकसद राष्ट्रपति को उस वर्ष अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन, विकास, कल्याण कार्यों की स्थिति के बारे में सूचित करना होता है। झारखंड जैसे राज्यों के इन प्रतिवेदनों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं का विवरण, लाभार्थियों की संख्या, खर्च का ब्यौरा और बजटीय आवंटन शामिल होता है।

लेकिन बहुतायत में ऐसे प्रतिवेदनों में इन क्षेत्रों में आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा, भूमि हश्तांतरण पर रोक, जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के कार्य या प्रदर्शन का कोई जिक्र नहीं होता। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, वन अधिकार, खनन जैसे महत्वपूर्ण कानूनों के जनजातीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों को भी प्रतिवेदन में नहीं दर्शाया जाता।

संविधान की अपेक्षाओं और व्यवहार में भारी अंतर रहा है। 2016 में जब झारखंड की राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण और टेनेंसी कानूनों में संशोधन का प्रयास किया, तब राज्यपाल को संविधान की रोशनी में आदिवासी हितों की रक्षा करनी थी। लेकिन राज्यपाल की भूमिका केवल औपचारिक रही। झारखंड में खनन और ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ दर्जनों आंदोलन हो रहे हैं लेकिन राज्यपाल मौन हैं। पेसा कानून राज्य में लागू नहीं है, राज्यपाल बेफिक्र हैं।

छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम और नक्सल हिंसा में हजारों निर्दोष आदिवासी मारे गए, गाँव के गाँव जला दिए गए, राज्यपाल के कान पर जूं नहीं रेंग। हँसदेव की जमीन लूट ली गयी, जंगल साफ हो गए, वनाधिकार को ठेंगा दिखाया जाता रहा लेकिन राजपाल ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। राज्य में पेसा कानून का

क्रियान्वयन राज्यपाल के संरक्षण में होना था, परंतु ग्राम सभाओं को अधिकार देने की प्रक्रिया लगातार अधूरी पड़ी रही।

ढेबर आयोग सहित अनेक आयोगों ने जनजातीय परामर्शदात्री परिषद को निष्क्रिय, कमजोर और अप्रभावी बताया है तथा इसे सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। साथ ही राज्यपालों की भूमिका की भी आलोचना हुई है कि वे संवैधानिक जिम्मेदारी के बावजूद प्रशासन की वाशतविक चुनौतियों पर पर्याप्त रिपोर्टिंग नहीं करते। 2015 में केरल ने पांच जिलों में 2,133 बश्तियों, पांच ग्राम पंचायतों और दो वार्डों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने का प्रशताव पारित किया था और इसे अब भी केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के मंजूरी का इंतजार है।

छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के राज्यों- असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा के लिए एक विशेष व्यवस्था करती है। इसमें स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है, जिनके पास भूमि, संस्कृति, न्याय, वन, संसाधन और शिक्षा से जुड़े व्यापक अधिकार निहित हैं। लेकिन इन परिषदों के निर्णयों के निरीक्षण और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी अंततः राज्यपाल पर डाल दी गई है। राज्यपाल यहां भी अंतिम निर्णायक बनते हैं कि कोई प्रशताव लागू होगा या नहीं। पूर्वोत्तर में जातीय संघर्ष और संसाधनों पर विवाद स्थायी समस्या बना हुआ है। छठी अनुसूची की परिषदों में बार-बार विवाद हुए, लेकिन गवर्नरों ने निर्णायक और संरक्षक की भूमिका शायद ही निभाई।

व्यवहार में देखा गया है कि राज्यपाल अक्सर इन परिषदों को न तो पर्याप्त अधिकारों के साथ कार्य करने देते हैं और न ही रिपोर्टिंग व निष्पक्ष निरीक्षण की अपनी भूमिका गंभीरता से निभाते हैं। परिणामस्वरूप, आदिवासी समाजों की वाशतविक आकांक्षाएं शासन व्यवस्था में पूर्णतः परिलक्षित नहीं हो पातीं।

सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 (जो कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति देता है) का उपयोग करते हुए निम्नलिखित समय-सीमाएँ तय कीं है। राज्यपाल को बिल पर सहमति देना या असहमति जताना है तो यह 1 महीने के अंदर करना होगा। अगर बिल मनी बिल (वित्तीय विधेयक) नहीं है, तो उसे वापस करने के लिए 3 महीने का समय है।

अगर बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा गया है, तो उस पर फैसला 3 महीने के अंदर होना चाहिए। अगर विधानमंडल ने बिल को दोबारा पारित करके राज्यपाल के पास भेजा है, तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर सहमति देनी होगी। अगर कोई देरी होती है, तो राज्यपाल को लिखित में कारण बताना होगा और इसे राज्य सरकार को सूचित करना होगा।

संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को बिल पर सहमति देने, सहमति रोकने, बिल को (मनी बिल को छोड़कर) वापस भेजने और बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने का विकल्प देता है।अनुच्छेद 201 उन बिल्स से संबंधित है जो राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजे जाते हैं। पहले इसमें कोई समय-सीमा नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने समय-सीमा तय कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी पहले सरकारिया आयोग (1988) और पुंछी आयोग (2007) ने सुझाव दिया था कि राज्यपालों को बिल्स पर फैसला करने के लिए समय-सीमा तय की जानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जानी चाहिए।

राज्यपाल की जबावदेही तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हश्तक्षेप किया है। शमशेर सिंह (1974) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना चाहिए। एस.आर. बोम्मई (1994) मामले में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल की भूमिका को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने का फैसला दिया गया। रामेश्वर प्रसाद (2006) के मामले में राज्यपाल के व्यक्तिगत विवेक को सीमित किया गया।

आदिवासियों की संवैधानिक सुरक्षा को नई ताकत

यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक मोड़ है। यह न केवल राज्यों को राहत देता है, बल्कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भी आशा की किरण है। अब समय है कि राज्यपाल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएँ।

राष्ट्रपति भी आदिवासी हितों से जुड़ी स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्टों पर ध्यान दें। केंद्र सरकार और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करें कि पाँचवीं और छठी अनुसूची के प्रावधान केवल किताबों में न रह जाएँ, बल्कि आदिवासी जीवन की असली ढाल बनें।

यह फैसला वाश्तव में भारत के संघीय ढाँचे को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन इसकी असली कसौटी यही होगी कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति अब सचमुच आदिवासी हितों और लोकतांत्रिक पारदर्शिता के संरक्षक बन पाते हैं या नहीं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि आदिवासी क्षेत्रों की सतत उपेक्षाः केवल समय-सीमा से समस्या हल नहीं होगी। लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न केवल केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन लाता है, बल्कि भारत के सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़े समुदायों आदिवासियोंकी संवैधानिक सुरक्षा को भी नई ताकत देता है।

ऑनलाइन गेमिंग बिल : "मनोरंजन, रोजगार और सामाजिक ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन की तलाश"

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत में डिजिटल क्रांति के बाद से मोबाइल और इंटरनेट ने जिस तरह लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, उसमें ऑनलाइन गेमिंग का संसार सबसे अधिक आकर्षक और विवादित रहा है। स्मार्टफोन की बढ़ती पहुँच, तेज़ इंटरनेट और युवाओं के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता ने इस क्षेत्र को तेजी से विश्तार दिया है। लेकिन जहाँ एक ओर ई-स्पोर्ट्स और कौशल-आधारित खेलों ने भारत को विश्व मानचित्र पर जगह दिलाई है, वहीं दूसरी ओर पैसे के दाँव पर खेले जाने वाले खेल, बेटिंग ऐप्स और जुए जैसी प्रवृत्तियों ने समाज और सरकार दोनों को चिंतित किया है।

इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी है। यह बिल न केवल आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि भविष्य में भारत की डिजिटल नीति की दिशा भी तय करेगा।

यह बिल स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी वाशतविक धन पर आधारित गेमिंग या ऑनलाइन सट्टेबाज़ी प्रतिबंधित होगी।

इसके साथ ही ऐसे खेलों के विज्ञापन, प्रचार और वित्तीय लेन-देन पर भी रोक लगाने का प्रावधान है। इसका सीधा मतलब है कि बैंक और वित्तीय संस्थान किसी भी रूप में ऐसे खेलों से जुड़े लेन-देन को प्रोसेस नहीं करेंगे। इस प्रावधान से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पैसे के लालच में जुए जैसी प्रवृत्तियाँ समाज में न फैलें।

परंतु इस बिल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ई-स्पोर्ट्स और कौशल-आधारित गैर-आर्थिक गेमिंग को बढ़ावा देता है। सरकार ने साफ किया है कि उसे खेल के रूप में ई-स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करना है।

आने वाले समय में 'नेशनल ई-स्पोर्ट्स अथॉरिटी' जैसी संस्था की स्थापना की जा सकती है, जो ई-स्पोर्ट्स को अंतरराष्ट्रीय शतर पर भारत का प्रतिनिधि बनाने की दिशा में काम करेगी। यह कदम न केवल डिजिटल खेलों को वैधता देगा बल्कि उन लाखों युवाओं को भी अवसर देगा जो गेमिंग को कैरियर बनाना चाहते हैं। इस बिल का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को केंद्रीय नियामक की भूमिका सौंपी गई है। मंत्रालय को यह अधिकार होगा कि वह गैर-पंजीकृत या अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सके। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों से बचाने के उद्देश्य से की गई है। भारत में अब तक ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियम अलग-अलग राज्यों में अलग थे। कहीं इसे वैध माना गया तो कहीं प्रतिबंधित। ऐसे में एक राष्ट्रीय शतर की रूपरेखा बनाना समय की मांग थी।

यह बिल केवल नियम-कानून का दश्तावेज़ नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि ऑनलाइन बेटिंग और वाशतविक धन से जुड़े खेलों की लत ने कई युवाओं की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं। कई मामलों में लोगों ने कर्ज़ लेकर खेला और परिवार तबाह हो गए।

बच्चों में भी मोबाइल गेम्स की लत मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रही है। सरकार को यह भी एहसास है कि इस समस्या को रोकना उतना ही ज़रूरी है जितना मादक पदार्थों की लत को रोकना। कई विशेषज्ञों ने तो इसे नशे से भी खतरनाक बताया है क्योंकि यह बिना किसी भौतिक पदार्थ के सीधे दिमाग़ पर नियंत्रण कर लेती है।

हालाँकि उद्योग जगत का पक्ष बिल्कुल अलग है। गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है कि इस बिल से लगभग दो लाख नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है और सरकार को हर साल मिलने वाले बीस हज़ार करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व पर भी असर पड़ सकता है।

'ड्रीम11', 'गेम्स24x7', 'विन्ज़ो' जैसी कंपनियाँ लंबे समय से करोड़ों रुपये का कारोबार कर रही हैं। उनका कहना है कि यदि घरेलू प्लेटफॉर्म को पूरी तरह रोक दिया गया तो उपयोगकर्ता विदेशी और ऑफशोर प्लेटफॉर्म की ओर रुख करेंगे, जहाँ न तो सरकार का कोई नियंत्रण होगा और न ही उपभोक्ताओं की सुरक्षा। इससे उल्टा नुकसान ही होगा।

इस बहस में दोनों पक्षों की अपनी-अपनी दलीलें हैं। सरकार का तर्क है कि समाज को जुए और नशे की लत से बचाना ज़रूरी है, वहीं उद्योग जगत मानता है कि यह क्षेत्र देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है और इसे खत्म करना युवाओं के रोजगार और नवाचार दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। असली चुनौती यही है कि सही संतुलन कैसे कायम किया जाए।

बिल के समर्थकों का कहना है कि इस कदम से न केवल सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। ई-स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देकर भारत अंतरराष्ट्रीय शतर पर मेडल जीत सकता है, जैसा कि हमने बैडमिंटन, कुश्ती या क्रिकेट में देखा है। इसके अलावा गैर-आर्थिक गेम्स को बढ़ावा देने से बच्चों का मनोरंजन भी सुरक्षित दायरे में रहेगा। दूसरी ओर आलोचकों का मानना है कि सरकार को 'पूर्ण प्रतिबंध' की बजाय 'कड़े नियमन' का राश्ता चुनना चाहिए था।

यदि धन-आधारित गेमिंग को लाइसेंस प्रणाली और कड़े कराधान के तहत नियंत्रित किया जाता तो न केवल सरकार को राजस्व मिलता बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी बनी रहती। पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से समस्या यह है कि लोग भूमिगत या विदेशी प्लेटफॉर्म की ओर भागेंगे और सरकार का नियंत्रण और भी कमजोर हो जाएगा।

यह बहस केवल भारत तक सीमित नहीं है। विश्व के कई देशों में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में इसे सख्त नियमों और टैक्स प्रणाली के तहत वैध किया गया है। वहीं चीन जैसे देशों ने बच्चों के लिए गेमिंग के समय पर ही पाबंदी लगा दी है। भारत ने अब तक इस दिशा में कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई थी, यही कारण है कि राज्यों के शतर पर भ्रम और असमानता बनी रही।

अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा? यह बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा और संभव है कि इसमें संशोधन हों। उद्योग जगत की चिंताओं को देखते हुए सरकार कुछ नरमी दिखा सकती है।

उदाहरण के लिए 'फैंटेसी स्पोर्ट्स' को कौशल-आधारित खेल मानकर सीमित अनुमति दी जा सकती है। इसी तरह कराधान और नियमन के ज़रिए सरकार और उद्योग के बीच समझौता हो सकता है।

परंतु एक बात तय है कि यह बिल भारत की डिजिटल यात्रा का अहम पड़ाव है। यह देश को यह सोचने पर मजबूर करता है कि तकनीक और समाज का संतुलन कैसे बनाया जाए।

तकनीक अपने आप में न अच्छी है न बुरी, उसका इश्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। यदि ऑनलाइन गेमिंग युवाओं को कैरियर, रोजगार और अंतरराष्ट्रीय पहचान दे सकती है तो यह सकारात्मक है। ‹

लेकिन यदि वही गेमिंग परिवारों को तोड़ दे, युवाओं को कर्ज़ में डुबो दे और अपराध को बढ़ावा दे, तो यह खतरनाक है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार, उद्योग, समाज और परिवार – सभी मिलकर समाधान निकालें। अभिभावकों को बच्चों पर नज़र रखनी होगी, शिक्षा संस्थानों को डिजिटल साक्षरता सिखानी होगी, उद्योग जगत को आत्मनियंत्रण और पारदर्शिता अपनानी होगी और सरकार को नियमन और प्रोत्साहन के बीच संतुलन बनाना होगा।

ऑनलाइन गेमिंग बिल केवल एक कानून नहीं है, यह हमारे समाज के भविष्य की रूपरेखा है। यह हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या हम डिजिटल क्रांति को सिर्फ मनोरंजन और जुए का साधन बनने देंगे या इसे शिक्षा, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का अवसर बनाएँगे।

आने वाले वर्षों में यह बिल किस रूप में लागू होगा और समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह बहस भारत के हर घर तक पहुँचेगी, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट अब हर जेब में है और गेमिंग हर उम्र की पसंद।

"इतिहास की सीख छोड़ फ्रेम में उलझा युवा वर्ग"

डॉ. प्रियंका सौरभ

पीढ़ी 1990 के बाद पैदा हुई, उसके हिस्से 'इतिहास' कम 'फ्रेम' ज्यादा आए। मोबाइल, कैमरा और सोशल मीडिया की दुनिया ने उन्हें घटनाओं की गहराई में जाने की बजाय केवल सतही फ्रेम और दृश्य-छवियों तक सीमित कर दिया।

आज का युवा वर्ग अतीत के संघर्षों से शिक्षा लेने के बजाय इंस्टेंट फ्रेमों में फँसा है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है।

आधुनिकता के उन्माद के बावजूद हमारे सार्वजनिक जीवन में जो शून्यता, दरिद्रता और दिशाहीनता दिखाई देती है, उसके कारण बहुत दूर जाकर नहीं खोजने पड़ते। यह शून्यता दरअसल हमारी स्मृतियों और सांस्कृतिक आत्मबोध के बिखराव से पैदा हुई है। इतिहास हमें बताता है कि क्या हुआ, जबकि साहित्य यह दिखाता है कि क्या हो सकता था और क्या होना चाहिए था। साहित्य को आत्मसत्य इसलिए कहा गया है कि वह मनुष्य को केवल सूचना नहीं, बल्कि अनुभव और मूल्य देता है।

भारत का इतिहास किसी सुखद घटनाओं की लड़ी नहीं है। इसमें युद्ध, संघर्ष, विद्वेष, विभाजन और बँटवारा है। लेकिन इन्हीं अंधेरे अध्यायों के बीच स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा भी है। 1857 से 1947 तक का काल केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, वह साहित्य का भी स्वर्णकाल था।

स्वतंत्रता संग्राम और साहित्य जैसे एक-दूसरे में घुल गए थे। कवि, लेखक और कलाकार केवल दर्शक नहीं थे, बल्कि वे इतिहास के सह-निर्माता थे। उनके गीत, कविताएँ और उपन्यास आम जनमानस में ऊर्जा और चेतना जगाते थे। यही कारण है कि आज़ादी की लड़ाई केवल तलवार और आंदोलन की गाथा नहीं रही, बल्कि साहित्यिक कृतियों की भी कहानी बनी।

लेकिन यह गौरवशाली परंपरा आज कहीं खो गई है। एक प्राचीन सभ्यता की प्राणवत्ता उसके सांस्कृतिक प्रतीकों और जीवनदायी आस्थाओं में निहित होती है। यही प्रतीक एक समय में हमारे चिंतन, सृजन और व्यवहार को अर्थ प्रदान करते थे।

जब यह जीवन्त समग्रता खंडित होकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाती है, तो वे केवल नामलेवा अनुष्ठानों तक सिमट जाते हैं। पूजा-पाठ तो बचा रहता है, परंतु उससे कोई नयी प्रेरणा नहीं निकलती। आज का भारतीय समाज इसी विडंबना से गुजर रहा है-हमारे पास परंपराएँ तो हैं, लेकिन उनमें जीवन्तता नहीं है।

हम अपने ही देश में आत्मनिर्वासित प्राणियों की तरह जीने को विवश हो गए हैं। हमारी नैतिक मर्यादाएँ, हमारे अध्ययन और हमारे विचार-सब पर विदेशी भाषा और सोच का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अंग्रेज़ी का वर्चस्व केवल एक शैक्षिक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक निर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक है।

हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा था-"अंग्रेज़ी भाषा ने संस्कृत का सर्वाधिकार छीन लिया है। आज भारतीय विद्याओं की जैसी विवेचना और विचार अंग्रेज़ी भाषा में हैं, उसकी आधी चर्चा का भी दावा कोई भारतीय भाषा नहीं कर सकती। यह हमारी सबसे बड़ी पराजय है। राजनीतिक सत्ता के छिन जाने से हम उतने नतमश्तक नहीं हैं, जितने अपने विचार की, तर्क की, दर्शन की, अध्यात्म की अपनी सर्वस्व भाषा छिन जाने से। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम अपनी ही विद्या को अपनी बोली में न कह सकने के उपहासास्पद अपराधी हैं। यह लज्जा हमारी जातीय है।"

वाश्तव में जिसे द्विवेदी जी ने 'उपहासास्पद अपराध' कहा, उसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार भारतीय सम्भ्रांत शिक्षित वर्ग रहा है। उसने अंग्रेज़ी को श्रेष्ठता और भारतीय भाषाओं को पिछड़ेपन का चिह्न बना दिया। आज स्थिति यह है कि युवा पीढ़ी अपनी ही भाषा में बोलने से हिचकती है, अपनी संस्कृति को आधुनिकता के विपरीत मानती है और साहित्य को केवल पाठ्यक्रम की किताबों तक सीमित समझती है। 1990 के बाद जन्मी पीढ़ी का संकट यही है। उनके पास सूचनाओं का अंबार है, पर आत्मसत्य नहीं। वे मोबाइल स्क्रीन पर इतिहास की झलकियाँ देखते हैं, पर उसकी गहराई में नहीं उतरते।

उनकी चेतना फ्रेमों और क्लिप्स पर आधारित है। इस पीढ़ी ने 'इतिहास' कम और 'फ्रेम' ज्यादा देखे हैं। यही कारण है कि उनमें वह गहराई नहीं है, जो साहित्य और इतिहास से संवाद करने पर आती।

इतिहास से हमें संघर्ष, धैर्य और त्याग की शिक्षा मिलती है। लेकिन फ्रेम हमें केवल तात्कालिक दिखावा और सतही आकर्षण देता है। यही वजह है कि युवा वर्ग की ऊर्जा दिशाहीन होती जा रही है। उनके पास विकल्प बहुत हैं, पर संकल्प नहीं। फ्रेम की दुनिया क्षणभंगुर है-एक फोटो, एक रील, एक क्लिक पल भर में आती है और मिट जाती है। जबकि इतिहास की सीख स्थायी है-वह आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा देती है।

यदि युवा वर्ग इस आत्मसत्य को समझने में असफल रहा, तो वह न केवल अपने वर्तमान को खो देगा बल्कि भविष्य को भी अंधकारमय कर लेगा।

साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। यह व्यक्ति और समाज को अपने आत्म से मिलाने वाला माध्यम है। साहित्य हमें बताता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं और हमारे सपनों का आकाश कहाँ तक फैला है। साहित्य के बिना समाज केवल सूचनाओं का ढेर रह जाता है, आत्मबोध और दिशा खो देता है। यही कारण है कि आज साहित्य को पुनः केंद्र में लाने की आवश्यकता है।

आज का प्रश्न यही है-क्या हम इस पीढ़ी को फिर से साहित्य और इतिहास से जोड़ पाएँगे? क्या हम उन्हें दिखा पाएँगे कि संस्कृति कोई बोझ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का आधार है? यह तभी संभव होगा जब भारतीय भाषाओं को केवल बोलचाल तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें ज्ञान और शोध की भाषा बनाया जाए।

नई पीढ़ी को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया के फ्रेम और क्लिक क्षणिक हैं। वे पल भर में आते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन साहित्य और संस्कृति वे आधार हैं, जिन पर स्थायी आत्मविश्वास खड़ा होता है। यह पीढ़ी तभी सार्थक होगी जब वह अपनी जड़ों से जुड़कर आधुनिकता को आत्मसात करेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो साहित्य केवल पुश्तकालयों में बंद रह जाएगा और संस्कृति केवल त्योहारों के सजावटी फ्रेम में कैद हो जाएगी। तब हम केवल उपभोक्ता समाज रह जाएँगे, सृजनशील सभ्यता नहीं।

आज आवश्यकता है कि विद्यालय और विश्वविद्यालय साहित्य को केवल परीक्षा का विषय न मानें, बल्कि जीवन का अनुभव मानें। लेखकों और कवियों को पुनः समाज के केंद्र में लाने की ज़रूरत है। भाषा को बोझ नहीं, गौरव का माध्यम बनाने की आवश्यकता है। और सबसे बढ़कर, नई पीढ़ी को यह एहसास दिलाना होगा कि साहित्य का आत्मसत्य ही वह शक्ति है, जो उन्हें इतिहास की गहराई और भविष्य की दिशा दोनों देता है।

इतिहास हमें यह दिखाता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। साहित्य हमें यह सिखाता है कि हम क्या हो सकते हैं। यही कारण है कि साहित्य और इतिहास का संबंध इतना गहरा और अविभाज्य है। यदि नई पीढ़ी इस आत्मसत्य से जुड़ने में असफल रही, तो वह न तो इतिहास समझ पाएगी और न ही भविष्य गढ़ पाएगी।

आधुनिकता का उन्माद तभी सार्थक होगा, जब वह साहित्य और संस्कृति की आत्मा से जुड़कर नई रचनात्मकता पैदा करेगा। अन्यथा हम केवल 'फ्रेम' की पीढ़ी रह जाएँगे-जहाँ गहराई नहीं होगी, केवल सतही छवियाँ होंगी। यही इस समय की सबसे बड़ी चेतावनी भी है और सबसे बड़ा समाधान भी।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती आशा शर्मा द्वारा 707 मंदाकिनी टावर सेक्टर -4, वैशाली गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) भारत से प्रकाशित एवं एन.सी.आर. प्रिंटर्स, 15/19 साइट-4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया जनपद गाजियाबाद से मुद्रित। **संपादक** : संजय शर्मा
फोन: 9899683800 वेबसाइट : www.khabariya.com **ई-मेल**: todayncr@gmail.com >> ncrtoday@hotmail.com **RNI**-UPHIN/2009/30721

अब दो दिन होगी सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा

प्रयागराज, एजेंसी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) मुख्य परीक्षा-2024 को दो दिन में आयोजित कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता 609 पदों पर भर्ती होनी है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा-2024 इस बार कई बदलावों के लिए चर्चा में है। पहले एक लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन होता था लेकिन आयोग ने पहली बार प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया। 20 अप्रैल 2025 को 173 केंद्रों पर आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में 31639 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में महज 40 फीसदी उपस्थिति थी।

आयोग ने 26 मई 2025 को प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में 7358 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया था। आयोग के कैलेंडर में मुख्य परीक्षा 28 सितंबर 2025 को प्रस्तावित थी लेकिन बुधवार को आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से इस आशय की विज्ञप्ति जारी कर दी गई कि मुख्य परीक्षा अब 28 व 29 सितंबर को दो सत्रों में सुबह 9:30 से दोपहर 12:00 व अपराह्न 2:30 से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा 750

अंकों की होगी। इसमें 375-375 अंकों के दो प्रश्नपत्र होंगे। दोनों प्रश्नपत्रों को हल करने के लिए ढाई-ढाई घंटे का वक्त मिलेगा। मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 125 सवाल होंगे। प्रथम प्रश्नपत्र में सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न के लिए तीन अंक यानी कुल 75 अंक और मुख्य विषय (सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, विद्युत व कृषि इंजीनियरिंग) से 100 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न के लिए तीन अंक यानी कुल 300 अंक निर्धारित होंगे। इसी प्रकार द्वितीय प्रश्नपत्र में तीन-तीन अंक के सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्न व तीन-तीन अंक के मुख्य विषय के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे जो 100 अंकों का होगा। मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू के कुल 850 अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी।

28 सितंबर 2025 को सिविल शाखा की परीक्षा होगी। सुबह 9:30 से दोपहर 12:00 बजे के पहले सत्र में सामान्य हिंदी व मुख्य विषय सिविल इंजीनियरिंग-1 और अपराह्न 2:30 से 5:00 के दूसरे सत्र में सामान्य अध्ययन व सिविल इंजीनियरिंग-2 की परीक्षा होगी।

29 सितंबर 2025 को अन्य शाखा की परीक्षा होगी। सुबह 9:30 से दोपहर 12:00 बजे के पहले सत्र में सामान्य अध्ययन व मुख्य विषय मैकेनिकल इंजीनियरिंग-1, विद्युत इंजीनियरिंग-1, कृषि इंजीनियरिंग-1 की परीक्षा और अपराह्न 2:30 से 5:00 के दूसरे सत्र में सामान्य अध्ययन व मुख्य विषय मेकैनिकल इंजीनियरिंग-2, विद्युत इंजीनियरिंग-2, कृषि इंजीनियरिंग-2 की परीक्षा होगी।28 सितंबर को राजस्थान में भी सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए अभियंत्रण सेवा की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश की अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे कई अभ्यर्थियों ने राजस्थान की परीक्षा के लिए भी आवेदन किए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को किसी एक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। अभ्यर्थी चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी जाए।

प्रो. दिव्या शर्मा ने बच्चों में न्यूरोमस्क्युलर गतिविधि पर अध्ययन पर शोध पत्र प्रस्तुत किया

✷ **एनसीआर टुडे. अलीगढ़** ✷। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डॉ. जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज के बाल एवं निवारक दंत चिकित्सा विभाग की प्रोफेसर दिव्या संजय शर्मा ने हाल में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के 5वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। उनका शोध पत्र "फंक्शनल मैंडिबुलर शिफ्ट वाले बच्चों में चबाने की मांसपेशियों की न्यूरोमस्क्युलर गतिविधिः एक एसईएमजी अध्ययन" शीर्षक पर आधारित था। यह शोध पत्र उनके पीएचडी शोध प्रबंध के एक पद्धतिगत घटक के मात्रात्मक सत्यापन पर आधारित था। यह अध्ययन डॉ. जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज के ऑर्थोडॉन्टिक्स विभाग की प्रोफेसर संध्या माहेश्वरी और जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की एर्गोनॉमिक्स प्रयोगशाला में किए गए इलेक्ट्रोमायोग्राफी शोध में मार्गदर्शन देने वाले प्रोफेसर आबिद अली खान के सहयोग से तैयार किया गया। प्रो. शर्मा ने सम्मेलन के दौरान एक वैज्ञानिक सत्र की अध्यक्षता भी की।

मृत गौवंश की सूचना पर प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

✷ **एनसीआर टुडे. अलीगढ़** ✷। मथुरा बाईपास रोड़ पर मृत गौवंश की सूचना पर विश्व हिन्दू परिषद बजरंगदल के कार्यकर्ता तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करने लगे। उन्होंने चौकी प्रभारी के ऊपर भी अनदेखी का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध जांच कराए जाने को कहा। क्योकि कई बार सूचना देने पर भी चौकी प्रभारी ने विषय को गंभीरता से नहीं लिया जिसके कारण यह घटना घटी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जहाँ गौपालन स्वयं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कर रहे हैं वहां अलीगढ़ के पुलिस अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की अनदेखी घोर निंदनीय है। चौकी प्रभारी के विरुद्ध भी शिकायती पत्र मडराक थाने में दिया गया। मौके पर विहिप महानगर स्वाबलंबन प्रमुख जितेंद्र आर्य की अगुवाई में देव सोनी ,भूपेंद्र सिंह,आदि कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। गौरक्षा दल से सचिन राघव भी कार्यकर्ताओं सहित थाना मडराक पर उपस्थित रहे।

महिला अस्पताल में चेहरा दिखाकर बायोमीट्रिक हाजिरी लगेगी

✷ **एनसीआर टुडे. गाजियाबाद** ✷। महिला अस्पताल में चिकित्सक और कर्मचारियों की चेहरा दिखाकर बायोमीट्रिक हाजिरी लगेगी। अस्पताल में चार स्थानों पर फेस रीडर मशीन लगाई गई है। इसका ट्रायल शुरू हो गया है। जिला महिला अस्पताल में लंबे समय से चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रजिस्टर में हस्ताक्षर कर खुद हाजिरी लगाते थे। कई स्वास्थ्य कर्मचारी मनमानी कर रहे थे। देर से आना, बिना बताए छुट्टी लेना या हस्ताक्षर करने के बाद चले जाना आम बात हो गई थी। इसको देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने फेस रीडर बायोमीट्रिक मशीन लगा दी है। मशीन के सॉफ्टवेयर में कर्मचारियों का डाटा अपलोड किया जा रहा है। इसमें स्थाई, संविदा कर्मचारी और ट्रेनी इंटर्न का डाटा भी अपलोड किया जा रहा है। फिलहाल अस्पताल के निचले तल पर ओपीडी में फार्मेसी के बाहर, इमरजेंसी, तीसरे तल पर प्रशासनिक कार्यालय और चौथे तल पर सभागार के बाहर मशीन लगाई गई है। जिला महिला अस्पताल की सीएमएस डॉ. अल्का शर्मा का कहना है कि उपस्थित में पारदर्शिता लगाने के उद्देश्य से मशीन लगाई गई है। कर्मचारियों का डाटा इसमें सेव किया जा रहा है। ट्रायल के रूप में मशीनों को शुरू कर दिया गया है। एक सप्ताह में मशीन शुरू हो जाएंगी।

कूड़े के विवाद में सफाई कर्मचारी पर हमला किया

✷ **एनसीआर टुडे. गाजियाबाद** ✷। साहिबाबाद थानाक्षेत्र में पूजा सामग्री वाले वाहन में घर का कूड़ा डालने से रोकने पर एक व्यक्ति ने सफाई कर्मचारी पर हमला कर दिया। जनकपुरी में गुरुवार सुबह पौने नौ बजे की घटना में सफाईकर्मियों ने काम रोककर साहिबाबाद थाने पर प्रदर्शन किया। आरोपी के पकड़े जाने पर कर्मचारी काम पर लौटे। जनकपुरी में मंदिरों से पूजा सामग्री का अपशिष्ट लेने के लिए निगम चालक विकास कूड़ा वाहन लेकर गए थे। पास में रहने वाला कुलदीप शर्मा घर का कूड़ा लाकर इस वाहन में डालने लगा तो सुपरवाइजर कुलदीप ने इसे रोका। उन्होंने कहा कि मंदिरों के अपशिष्ट को अलग निश्तारित किया जाता है। इसमें कूड़ा न डालें। इस पर आरोपी ने जातिसूचक टिप्पणी करते हुए गाली दी और विरोध पर मारपीट करने लगा। इसमें सुपरवाइजर के कपड़े फट गए।

सीएम योगी ने किया सीमेंट संयंत्र का शुभारंभ, बोले- अब बदल रही उत्तर प्रदेश की तस्वीर

एटा, एजेंसी। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा में विकास को नया आयाम दिया। उन्होंने मलावन क्षेत्र में श्री सीमेंट प्लांट दूसरी बड़ी परियोजना का शुभारंभ किया। ये ऐसी परियोजना है जो एटा को पूरे देश में पहचान दिलाएगी। साथ ही इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

सीएम योगी गुरुवार को एटा पहुंचे। यहां उन्होंने सीमेंट प्लांट का शुभारंभ किया। इस प्लांट में बड़े स्तर पर सीमेंट तैयार किया जाएगा। इसकी आपूर्ति देशभर में की जाएगी। इससे एटा का नाम भी पूरे देश में पहचाना जाएगा। इससे पहले मलावन क्षेत्र में ही जवाहरपुर विद्युत तापीय परियोजना भी स्थापित की जा चुकी है। इसकी दोनों इकाइयों से करीब 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इससे भी एटा को देशभर में पहचान मिली है। सीएम योगी ने कहा कि जब सरकार की नीति स्पष्ट और नियत साफ हो तो इस तरह के परिणाम नजर आते हैं, जैसा आज एटा में दिख रहा है। नौ साल पहले की स्थिति को याद करें, जब गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। ऐसी सरकारें कल्याण के लिए क्या काम करेंगी। मुगल और अंग्रेजों के बाद देश और प्रदेश को कांग्रेस और सपा ने तबाह करने का काम किया है। सपा सबका साथ तो लेती थी लेकिन विकास केवल अपने परिवार का करती थी। 17वी 18 वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था नंबर एक की थी। आजादी के बाद सन् 43 से 60 तक छठे नंबर की अर्थव्यवस्था रही है।

सीएम योगी ने कहा कि 2014 में मोदी आए तब भारत 11 स्थान पर पहुंच चुका था। अथक प्रयासों से अब भारत नंबर चार की अर्थव्यवस्था बन गया है। अगले दो वर्षों में तीसरी श्रेणी में होगा। यूपी में 2017 से पहले निवेश भाग रहा था। अब हमने 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव लाने में सफलता हासिल की है। 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर आ चुके हैं, जिनसे 7 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। श्री सीमेंट प्लांट से एटा को यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2023 में मजबूती मिली थी। पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी इन्वेस्टर्स समिट का एलान किया। हर जिले में अधिकाधिक निवेश वाली परियोजनाओं को आकर्षित करना था। ऐसे में 600 करोड़ की इस परियोजना से एटा का पलड़ा काफी भारी हो गया था।

नोरा फतेही जैसी दिखने के लिए पत्नी से जबरन कराता था घंटों व्यायाम

✷ **एनसीआर टुडे. गाजियाबाद** ✷

जिले में एक अजीबोगरीब मामले में एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही की तरह दिखने के लिए जबरन घंटों तक सख्त व्यायाम कराने और इससे इनकार करने पर खाना नहीं देने व दहेज उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी शादी छह महीने पहले हुई थी। उसके परिवार ने शादी पर 76 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किये थे। इसके बावजूद उसका पति और ससुराल के अन्य लोग उसे दहेज के लिए परेशान करते थे। साथ ही महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति उसकी शारीरिक बनावट को लेकर लगातार ताने मारता था तथा वह उसे ''मोटी और बदसूरत'' भी कहता था। उसका पति एक सरकारी स्कूल में शारीरिक शिक्षा का अध्यापक है। शिकायत में कहा गया है कि उसका पति और ससुराल वाले उससे कथित तौर पर रोज़ाना तीन घंटे कसरत करने की मांग करते थे।

नाबालिग हिंदू लड़की को युवक ने प्रेम जाल में फंसाया

आरोपी ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया

✷ **एनसीआर टुडे. अलीगढ़** ✷

नाबालिग हिंदू लड़की को गैर समुदाय के युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। शादी करने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद आरोपी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। जब लड़की ने धर्म परिवर्तन करने से मना किया तो आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया।

वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला खुला और पीड़ता के परिजनों ने हिंदूवादियों की मदद से थाने पहुंचकर आरोपी की शिकायत की। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है।

जट्टारी कस्बे के रहने वाली एक नाबालिग हिंदू लड़की की इलाके में ही रहने वाले आसिफ से दोश्ती हो गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया। जिसके बाद आरोपी शादी करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था।

आरोपी ने लड़की के कई वीडियो बना लिए थे। जिसके बाद आरोपी ने लड़की के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। जब लड़की को इसकी जानकारी हुई तो उसने सारी जानकारी परिवार के लोगों को दी। जिसके बाद लोगों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़तिों ने आरोप लगाया कि आरोपी आए दिन गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देता था।

मामले की जानकारी होने के बाद परिवार के लोगों ने थाने में शिकायत की। जब यह मामला हिंदूवादियों को पता चला तो वह थाने पहुंच गए और तत्काल कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। सीओ वरुण सिंह ने बताया कि पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। उसकी जानकारी के कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी ही आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अब मकानों से भी चलेगा कारोबार, 50 हजार लोगों को मिलेगा फायदा

प्रयागराज, एजेंसी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने निर्माण एवं विकास उपविधि में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने जहां का लेआउट पास है, वहां के 100 वर्ग मीटर के भवन स्वामियों को भी नौ, 12, 18 और 24 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी है। इस फैसले से शहर के करीब 50 हजार से अधिक मकान मालिकों को लाभ मिलेगा।

मास्टर प्लान 2031 लागू होने के बाद प्रदेश भर में मॉडल बिल्डिंग बायलॉज एक समान हो गए हैं। पहले अलग-अलग प्राधिकरणों में अलग नियम थे। नए प्रावधान के तहत 24 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित मिश्रित भूखंड का मकान मालिक अब अपने मिश्रित भूखंड भू-उपयोग वाला मानचित्र स्वीकृत कराकर दुकानें या छोटे कारोबार शुरू कर सकेंगे। जिन लोगों ने पहले से अपने घरों में दुकानें खोली हैं, उन्हें अब आसानी से स्वीकृति मिल जाएगी।

जिस मकान के सामने नौ, 12, 18 या 24 मीटर चौड़ी सड़कें हैं, वहां भी वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। नए नियम से बड़ी आबादी लाभान्वित होगी और किराना स्टोर, स्टेशनरी, रेस्टोरेंट, होटल, शापिंग मॉल समेत छोटे व्यवसाय आसानी से शुरू हो सकेंगे।

इस निर्णय से पीडीए की आय में भी बढ़ोतरी होगी। व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक होगा। जहां का लेआउट पास हैं वहां एक रुपये जमा कर मानचित्र स्वीकृत करा सकेंगे। जिन्होंने पहले से दुकानें खोली है, उन्हें भी मानचित्र पास कराना होगा।

बाल वाटिका के बच्चों की शिक्षण सामग्री के लिए 53 करोड़ स्वीकृत, गतिविधि कैलेंडर भी किया जारी

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में पहले से चल रहे को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र व नई शुरू हुई बालवाटिका के बच्चों को पठन-पाठन से जुड़ी पर्याप्त शिक्षण सामग्री मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) ने 53074 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र व बालवाटिका के लिए 53 करोड़ स्वीकृत किए हैं।

इसके तहत बच्चों के प्रयोग के लिए कलर पेंसिल, एचबी पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, कलर्ड चॉक, हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी अल्फाबेट आदि लिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इन केंद्रों के लिए 52 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर जारी करते हुए तीन से छह साल के बच्चों को पढ़ाई के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से सभी बीएसए को निर्देश दिया गया है कि एआरपी, एसआरजी व डायट मेंटर अपने निर्धारित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में इसको लागू करेंगे। वहीं

शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्षता वाली कमेटी होगी। वहीं जिला समन्वयक प्रशिक्षण की ओर से इसका अनुश्रवण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नोडल शिक्षक संकुल विद्यालय परिसर के आंगनबाड़ी केंद्रों व बालवाटिका का बेहतर संचालन सुनिश्चित कराएंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि विद्यालयों में पूरी यूनिफॉर्म में सबसे अधिक उपस्थित रहने वाले छात्र का एक पूर्ण यूनिफॉर्म में फोटो फ्लेक्स पर प्रिंट कराकर कक्षा के बाहर लगाया जाना सुनिश्चित कराएं। इससे संबंधित व्यय विद्यालय की कंपोजिट ग्रांट से वहन किया जाएगा। इससे अन्य बच्चे भी यूनिफार्म में आने के लिए प्रेरित होंगे।

23 को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवसः प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि इसका उद्देश्य बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक करना है। इस दिन विशेष सभा, प्रदर्शनी, कार्यशाला व वैज्ञानिकों से संवाद भी आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी की ओर से इसके लिए ऑनलाइन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है।

शोहदों की धमकी से डरी मां ने दी जान, बेटी संग हुई थी छेड़खानी; मुख्य आरोपी की पानी में डूबने से हुई थी मौत

चित्रकूट, एजेंसी। चित्रकूट के मानिकपुर में फर्जी मुकदमे में फंसने के डर से बुधवार की शाम एक महिला ने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला की बेटी से 11 अगस्त को छेड़छाड़ हुई थी। इस पर महिला ने छह युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

बाद में घटना के मुख्य आरोपी की पानी में डूबने से मौत हो गई। महिला के परिजनों का आरोप है कि आरोपी महिला पर युवक की हत्या कराकर शव फेंकने का आरोप लगा रहे थे। साथ ही महिला से रुपये की मांग कर रहे थे। इससे महिला सहमी हुई थी। मानिकपुर कस्बे की एक किशोरी ने बताया कि आरोपी अमित कोल ने 11 अगस्त को कोचिंग जाते समय छेड़खानी की थी। उसने मां के साथ पुलिस से इसकी शिकायत की थी। अमित और पांच अज्ञात शोहदों के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 16 अगस्त को तुलसी जल प्रपात में नहाते समय अमित की डूबने से मौत हो गई। किशोरी ने बताया कि अमित की मौत के बाद उसके परिजन हमारे परिजनों पर दबाव बनाकर रुपये मांग रहे थे। वह अमित की हत्या कर पानी में शव फेंकने के आरोप के मुकदमे में फंसाने की बात कह रहे थे। थाना प्रभारी श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि मृतक अमित व पांच अज्ञात के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज है। महिला की मौत को लेकर कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अमित के परिजनों ने भी उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

हाईवे पर काल बनकर धमाचौकड़ी करते मवेशी

उन्नाव , एजेंसी।

लखनऊ-कानपुर हाईवे पर काल बनकर छुट्टा मवेशी धमाचौकड़ी करते हैं। इससे वाहन सवार परेशान हैं। दिन हो या रात भल्लाफार्म और सोहरामऊ के पास हाईवे पर मवेशियों का ठिकाना बन गया है। कब किस वाहन के सामने आ जाएं कुछ पता नहीं। आए दिन मवेशियों की धमाचौकड़ी के चलते हादसे होते हैं।

हाईवे पर सोहरामऊ, सोहरामऊ कस्बा, भल्लाफार्म और अजगैन कोतवाली के आसपास छुट्टा मवेशी दिन हो या रात कभी भी देखे जा सकते हैं। स्थिति यह है कि मवेशियों का यही ठिकाना बन गया है। यह ठिकाना वाहन सवारों के लिए खतरा बना है। यह हाल तब है जब हाईवे किनारे रसूलपुर, महनौरा, मलाव, जगदीशपुर, मखदुमपुर, रुदवारा और नदौहा गांव में गोशालाएं बनी हैं।

बावजूद इसके मवेशियों को संरक्षित करने के बजाए छोड़ा जा रहा है। अचानक से मवेशी आने से वाहन सवार कभी अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो कभी वाहन की रफ्तार धीमी करते हैं। इससे दूसरे वाहन से टकराने का खतरा भी बना रहता है। बीडीओ मुनेशचंद्र ने बताया कि वह मवेशियों को संरक्षित कराने के लिए अभियान चलाते रहते हैं। हाईवे पर मवेशियों के घूमने का पता चला है। इन सभी को संरक्षित कराया जाएगा।

पहले सिस्टम सुधारें...फिर बिजली दरों पर करें बात

लखनऊ , एजेंसी। बिजली दरों के निर्धारण की चल रही सुनवाई के तहत बुधवार को उप्र. पॉवर ट्रांसमिशन व यूपीएसएलडीसी ने पक्ष रखे। इस दौरान उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि पहले ट्रांसमिशन के सिस्टम (उपकरणों) का भार सही किया जाए फिर बिजली दर व ट्रांसमिशन चार्ज बढ़ाने की बात की जाए।

विद्युत नियामक आयोग में अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह की उपस्थिति में पॉवर ट्रांसमिशन के अधिकारियों ने प्रजेंटेशन दिया। इसके बाद उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पॉवर ट्रांसमिशन ने इस बार अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक

राजस्व आवश्यकता 6279 करोड़ दाखिल किया है। यह जनता पर भार डालने की साजिश है।

इस पर आयोग को गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्मा ने कहा कि पहले उपकरणों की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि गर्मी में पीक ऑवर्स में डायवर्सिटी फैक्टर 1:1 होते ही इनका सिस्टम कांपने लगता है। ऊपर से बिजली चोरी का लोड भी इसी सिस्टम पर आता है। ऐसे में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को सुचारु रूप से 24 घंटा बिजली नहीं मिल पाती है। वर्मा ने कहा कि यूपीएसएलडीसी स्वतंत्र होकर काम करे। आज भी केंद्र सरकार के बनाए कानून के तहत 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के मामले पर यूपीएसएलडीसी चुप रहता है। उन्होंने पॉवर ट्रांसमिशन के टैरिफ पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि सबसे पहले पॉवर ट्रांसमिशन सिर्फ रिटर्न ऑफ इक्विटी लाभांश 2त्न लेता था। इस बार 14.5त्न लेने की बात कही गई है। इससे उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर 1824 करोड़ का भार आएगा। अगर आयोग इसे मंजूर करता है तो टैरिफ बेस कॉम्पिटेटिव बिडिंग की प्रक्रिया जो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है।

पाकिस्तान की टीम की तरह उसका कप्तान भी फिसड्डी, सवालों के घेरे में सलमान आगा की कप्तानी

नई दिल्ली, एजेंसी। एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टी20 टीम का एलान हो चुका है। नौ सितंबर से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टीम की कमान सलमान अली आगा को सौंपी है, जिनका टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर अब तक फ्लॉप ही रहा है। इस टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे स्टार खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि पीसीबी ने दोनों को इस प्रारूप की रणनीति से साइडलाइन कर दिया है।

लय से बाहर चल रही टीम

पाकिस्तान के 17 सदस्यीय स्क्वॉड में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है। हालांकि, टीम अभी लय से बाहर चल रही है। हाल ही में उन्हें बांग्लादेश दौरे पर तीन मैचों की टी20 सीरीज में मुंह की खानी पड़ी थी। इसके बाद टीम ने वापसी की और वेस्टइंडीज को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में हराया। हालांकि, टी20 सीरीज की हार का बदला वेस्टइंडीज की टीम ने वनडे सीरीज में जीत के साथ लिया। ऐसे में पाकिस्तान का एशिया कप में सफर कैसा होगा, इस पर चर्चा तेज है।

पाकिस्तान के मुकाबले

पाकिस्तान की टीम अपने अभियान की शुरुआत 12 सितंबर से ओमान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इसके बाद उसका सामना दुबई में भारत से होगा। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान की टीम तीसरा मैच यूएई के खिलाफ खेलेगी, जो दुबई में ही 17 सितंबर को खेला जाएगा। सुपर-4 के मुकाबले 20 सितंबर से शुरू होंगे जबकि फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा।

इन आंकड़ों के आधार पर चुना कप्तान?

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के टी20 करियर की बात करें तो उनके आंकड़े बिल्कुल भी कप्तानी के लायक नहीं हैं। 20 मुकाबलों में उन्होंने कुल 380 रन बनाए हैं, यानी मुश्किल से औसत 27.1 का रहा है। टी20 जैसे प्रारूप में जहां बल्लेबाजों से 140-150 के स्ट्राइक रेट की उम्मीद की जाती है, वहां आगा मुश्किल से 115.8 के स्ट्राइक रेट को छू सके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी सिर्फ 56 रन ही है। वहीं, गेंदबाजी की बात करें तो 20 मैचों में उन्होंने सिर्फ चार विकेट झटके हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1/7 का है।

अब कप्तानी पर नजर डालें तो आगा ने 18 मैचों में पाकिस्तान की कमान संभाली, जिसमें नौ जीते और इतने ही हारे। यानी न टीम आगे बढ़ पाई, न कोई स्थिरता आई। उनकी कप्तानी में कोई बड़ा बदलाव या आक्रामक रणनीति नजर नहीं आई। इन आंकड़ों से साफ है कि सलमान अली आगा न बल्लेबाजी में धमाल मचा पाए हैं, न गेंदबाजी में और न ही कप्तानी में कोई करिश्मा दिखा पाए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किन आधारों पर उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया?

पांच खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार की सिफारिश

इनमें 4 पेरिस ओलिंपिक के मेडलिस्ट, वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश का भी नाम

मनु भाकर
शूटिंग
2 ब्रॉन्ज

सरबजोत सिंह
शूटिंग
ब्रॉन्ज

स्वप्निल कुसाले
शूटिंग
ब्रॉन्ज

अमन सहरावत
रेसलिंग
ब्रॉन्ज

नई दिल्ली (एजेंसी)। खेल मंत्रालय ने पांच खिलाड़ियों के नाम पद्म पुरस्कारों के लिए नामित किए हैं। इनमें चार खिलाड़ी मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुशाले और अमन सहरावत पेरिस ओलिंपिक के मेडलिस्ट हैं। वहीं, एक नाम चेस के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी. गुकेश का है। मंत्रालय के सूत्रों ने मीडिया को यह जानकारी दी है। मंत्रालय की ओर से ये नाम पद्म पुरस्कार समिति के पास भेजे गए हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 1 मई से 15 सितंबर के बीच करना होता है। पुरस्कार समिति 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के मौके पर पुरस्कारों की घोषणा करती है। पिछले साल पूर्व हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश को पद्म भूषण और दिग्गज स्पिनर आर अश्विन पद्मश्री मिला था।

मनु-गुकेश समेत 4 प्लेयर्स को खेल रत्न मिला था – 8 महीने पहले 17 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था।

नीरज-श्रीजेश को पहले मिल चुका है पद्म पुरस्कार

भारत ने पिछले साल अगस्त-सितंबर में आयोजित पेरिस ओलिंपिक गेम्स में 6 मेडल जीते थे। इनमें एक सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज शामिल रहे। पेरिस में भारत को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ियों में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश को पद्मभूषण मिल चुका है। नीरज चोपड़ा को 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री प्रदान किया था। पद्म पुरस्कार समिति का गठन हर साल प्रधानमंत्री करते हैं। कैबिनेट सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 मेंबर शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं।

एशिया कप में पाकिस्तान से खेलेगा भारत

सरकार ने कहा- मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में खेलने पर रोक नहीं, द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबले का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने गुरुवार को कहा है- 'मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने पर रोक नहीं है।' मंत्रालय ने यह भी कहा कि बाइलैटरल सीरीज में इंडिया का स्टैंड बरकरार रहेगा। खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने मीडिया से एक लेटर साझा किया, इसमें इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भारत की पॉलिसी बताई गई है। इसके अनुसार, भारतीय टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेंगी और न ही पाकिस्तान की टीमों को भारत में खेलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन, इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल इवेंट्स (चाहे भारत में हों या विदेश में) में भारत इंटरनेशनल खेल संस्थाओं के नियमों और अपने खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा। भारतीय टीमें और भारतीय खिलाड़ी उन इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे, जिनमें पाकिस्तान की टीमें और खिलाड़ी भी शामिल होंगे। यह ठीक वैसा ही है, जैसे भारत में होने वाले मल्टीनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की टीमें और खिलाड़ी भी भाग ले सकेंगे।

2 दिन पहले 19 अगस्त को बीसीसीआई ने एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद क्रिकेट एशिया कप में भारत के पाकिस्तान से खेलने का विरोध हो रहा है। इस संबंध में सदन में भी सवाल उठा था। पूर्व क्रिकेटर्स की भारतीय टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (डब्ल्यूसीएल) में पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया था।

इस साल भारत क्रिकेट एशिया कप का मेजबान है। पाकिस्तान के भारत में खेलने से इनकार के बाद इसे ,श्व में आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 10 सितंबर को ,श्व से होगा।

भारत-पाकिस्तान के 3 मुकाबले हो सकते हैं

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच 3 मुकाबले हो सकते है। पहला मैच 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

दूसरा मैच- एशिया कप में लीग स्टेज के बाद सुपर-4 राउंड होगा। भारत-पाकिस्तान के सुपर-4 राउंड में पहुंचने पर 21 सितंबर को भारत-पाकिस्तान की दूसरी भिड़ंत हो सकती है।

तीसरा मैच – अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं, तो 28 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप में तीसरा मुकाबला खेला जाएगा।

क्या पाकिस्तान से खेलना भारत की मजबूरी, बीसीसीआई ने बताए न खेलने के 4 नुकसान

पाकिस्तान से आए आतंकियों ने भारत पर बड़ा हमला किया था। इस घटना के कुछ ही महीनों बाद भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट सीरीज खेलनी थी। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू किया। वे पूछते - जो पाकिस्तान हमारा खून बहा रहा है उसके साथ हम क्रिकेट क्यों खेलना चाहते हैं? इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से खेल मंत्रालय को निर्देश आता है कि वे बीसीसीआई को कह दें कि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगी। यह वाकया 2008 का है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 26 नवंबर को मुंबई में बड़ा हमला किया था। इसके बाद दिसंबर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के साथ किसी भी द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज पर रोक लगा दी थी।अब सीधा 2025 में लौटते हैं। पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। पिछले 22 अप्रैल को वहां से आए आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोषों की धर्म पूछकर हत्या कर दी। इसके बाद मांग उठने लगी है कि भारत को अब न सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज बल्कि एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे मल्टी नेशनल इवेंट में भी पाकिस्तान का बायकॉट करना चाहिए। 9 सितंबर से यूएई में एशिया कप होना है। भारतीय टीम घोषित हो गई है और इस टूर्नामेंट में तीन भारत-पाकिस्तान मैच संभव हैं। पाकिस्तान से खेलने या न खेलने पर सरकार की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि, बीसीसीआई नहीं चाहता कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान का बायकॉट करे। मीडिया ने इस मुद्दे पर बीसीसीआई के दो शीर्ष अधिकारियों से इसकी वजह पूछी। दोनों ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर 4 ऐसे कारण बताए जिनकी वजह से बीसीसीआई अब भी चाहता है कि एशिया कप हो और इसमें भारत-पाकिस्तान मुकाबले भी खेले जाएं...।

रोहित मैदान पर वापसी को बेकरार

इस टीम के खिलाफ जलवा बिखेरते आ सकते हैं नजर

मुंबई, एजेंसी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब टीम इंडिया को दिलाने वाले कप्तान रोहित शर्मा की नीली जर्सी में वापसी का बेसब्री से इंतजार क्रिकेट प्रेमियों को है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से रोहित शर्मा ने कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। लेकिन अब उनकी टीम इंडिया में वापसी की संभावना ऑस्ट्रेलिया दौरे (19 अक्टूबर से) के दौरान दिखाई दे रही है। हालांकि, रोहित शर्मा इस दौरे से पहले ही एक खास सीरीज में हिस्सा लेने की इच्छा जता चुके हैं, जो कानपुर में खेली जाएगी।

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ खेलने की इच्छा

टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसमें भारतीय टीम 3 वनडे और 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। इस वनडे सीरीज के लिए टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली के शामिल होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ कानपुर में होने वाली अनऑफिशियल वनडे सीरीज में खेलने की इच्छा जताई है। ऑस्ट्रेलिया-ए सितंबर में भारत दौरे पर आएगी, जहां वे भारत-ए टीम के साथ दो अनऑफिशियल टेस्ट और तीन वनडे मैच खेलेंगी। दोनों टेस्ट मैच लखनऊ में आयोजित होंगे, जबकि तीनों वनडे मैच कानपुर में खेले जाएंगे।

विजय हजारे ट्रॉफी में भी खेलेंगे रोहित

रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि रोहित शर्मा इस अनऑफिशियल वनडे सीरीज में खेलने के इच्छुक हैं ताकि वे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। इसके अलावा खबरें हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज उनके वनडे करियर की आखिरी सीरीज हो सकती है। बीसीसीआई रोहित को दिसंबर 2025 में शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकता है, ताकि वे वनडे टीम में अपनी जगह बनाए रखें।

वनडे में रोहित शर्मा का शानदार रिकॉर्ड

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली है। अब तक उन्होंने 273 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें 265 पारियों में 48.76 की औसत से 11,168 रन बनाए हैं। इसमें उनके 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं। रोहित का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन है, जो वनडे इतिहास के सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर में से एक है।

रेड्डी ने विराट के साथ बिताए अपने खास पल का किया खुलासा

नितीश कुमार रेड्डी भारतीय क्रिकेट में तेजी से आगे बढ़े और जल्द ही उन्हें टी20 और टेस्ट कैप मिल गई। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली टी20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया में इस ऑलराउंडर ने विराट कोहली के साथ खेला, जो अंतत: दिल्ली के इस महान बल्लेबाज की आखिरी टेस्ट सीरीज साबित हुई। नितीश रेड्डी को विराट कोहली से अपनी पहली टेस्ट कैप मिली और अब आंध्र प्रीमियर लीग के दौरान एक साक्षात्कार में नितीश रेड्डी ने कहा कि यह उनके आदर्श के साथ उनका सबसे खास पल है। भीमावरम बुल्स के कप्तान भी विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, जब उन्होंने एडिलेड में अपना आखिरी टेस्ट शतक बनाया था और इसे एक और खास पल बताया। क्रके दौरान उन्होंने कहा, विराट भैया ने मुझे जो टेस्ट डेब्यू कैप दी थी, वह मेरे लिए एक बेहद खास पल था और एक और खास पल, विराट भैया का आखिरी टेस्ट शतक मैं उन्हें देखने के लिए नॉन-स्ट्राइकर एंड पर मौजूद था। इस तरह नितीश रेड्डी ने एक बार फिर विराट कोहली के प्रति अपने प्यार का इजहार किया है। इससे पहले भी इस ऑलराउंडर ने विराट कोहली के प्रति अपने लगाव का इजहार किया है और कहा है कि पूर्व भारतीय कप्तान और आरसीबी सुपरस्टार के साथ खेलना उनका सपना था। नितीश रेड्डी अब उम्मीद कर रहे होंगे कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अच्छी शुरुआत को आगे बढ़ाएं और लंबे समय तक देश की सेवा करें। वह हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन चोटिल हो गए।

आईसीसी ने रैकिंग में हुई गलती पर सफाई दी, बोला- गलती की जांच हो रही

यूएई (एजेंसी)। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस?िल (आईसीसी) ने बुधवार (20 अगस्त) को खिलाड़ियों की रैंकिंग अपडेट की, लेकिन इसमें एक बड़ा ब्लंडर कर दिया। वनडे रैंकिंग में रोहि?त शर्मा और विराट कोहली के नाम गायब थे। पिछले हफ्ते 13 अगस्त को जारी रैंकिंग में दोनों भारतीय बल्लेबाज टॉप-5 में शामिल थे। हालांकि, आईसीसी ने चार घंटे बाद ही गलती में सुधार किया और रैकिंग अपडेट कर दी। अब आईसीसी ने इस मामले में सफाई दी है।

एशिया कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान, सलीमा टेटे को मिली कप्तानी

नई दिल्ली (एजेंसी)। अनुभवी मिडफील्डर सलीमा टेटे को चीन के हांगझोउ में पांच से 14 सितंबर तक होने वाले एशिया कप के लिए बृहस्पतिवार को 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बरकरार रखा गया। यह टूर्नामेंट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका विजेता 2026 एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेगा। भारत को पूल बी में रखा गया है जहां उसका सामना जापान, थाईलैंड और सिंगापुर से होगा।

टीम अपने अभियान की शुरुआत 5 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ करेगी और फिर छह सितंबर को जापान से भिड़ेगी। भारत अपना अंतिम पूल मैच आठ सितंबर को सिंगापुर के खिलाफ खेलेगा। हॉकी इंडिया द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने कहा, 'हांगझोउ में होने वाले महिला एशिया कप के लिए हमने जो टीम चुनी है उसे लेकर हम उत्साहित हैं।

सलीमा पिछले साल कप्तान नियुक्त होने के बाद से टीम का अभिन्न अंग रही हैं। हरेंद्र ने कहा, 'यह टीम कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण ले रही है और हमने अनुभवी खिलाड़ियों तथा युवा प्रतिभाओं के बीच सही संतुलन बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, 'हमारा ध्यान आक्रामक और अनुशासित हॉकी खेलने पर होगा और

हमारा मानना ??है कि यह टीम एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ मजबूती से मुकाबला करने की क्षमता रखती है।

टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण है जिसमें गोलकीपिंग की जिम्मेदारी बंसारी सोलंकी और बिचु देवी खारीबाम पर होगी। रक्षा पंक्ति में निक्की प्रधान और उदिता जैसी अनुभवी खिलाड़ी होंगी जिनका साथ युवा मनीषा चौहान, ज्योति, सुमन देवी थोडम और इशिका चौधरी देंगी। मिडफील्ड में नेहा, सलीमा, लालरेमसियामी, शर्मिला देवी, सुनेलिटा टोप्पो और वैष्णवी विट्ठल फाल्के जैसी मजबूत खिलाड़ी हैं।

अग्रिम पंक्ति में अनुभवी और उभरते सितारों का मिश्रण है जिसमें नवनीत कौर, संगीता कुमारी, मुमताज खान, दीपिका, ब्यूटी डुंगडुंग और रुतजा दादासो पिसल शामिल हैं।

महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम

गोलकीपर – बंसारी सोलंकी, बिचु देवी खारीबाम

डिफेंडर – मनीषा चौहान, उदिता, ज्योति, सुमन देवी थोडम, निक्की प्रधान, इशिका चौधरी

मिडफील्डर –नेहा, वैष्णवी विट्ठल फाल्के, सलीमा टेटे, शर्मिला देवी, लालरेमसियामी, सुनेलिटा टोप्पो

फारवर्ड – नवनीत कौर, रुतजा दादासो पिसल, ब्यूटी डुंगडुंग, मुमताज खान, दीपिका और संगीता कुमारी।